हिन्दी पाक्षिक

सेमन्या कण्वघाटी

RNI No.: UTTHIN/2013/54659

वर्ष-12 अंक-03 हरिद्वार, रविवार, 15 दिसम्बर, 2024 मूल्य-दो रूपया मात्र पृष्ठ-8

ग्रीन गेम्स की थीम पर होंगे उत्तराखण्ड में नेशनल गेम्स

देहरादून । उत्तराखण्ड में 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए सभी तैयारियां बेहतर व्यवस्थाओं के साथ पूर्ण की जाएं। राष्ट्रीय खेल का आयोजन प्रदेश के लिए न केवल गौरव का विषय है, बल्कि यह प्रदेश की खेल संस्कृति और विकास को प्रोत्साहन देने का भी महत्वपूर्ण अवसर है। राष्ट्रीय खेल उत्तराखण्ड को खेल भूमि के रूप में भी स्थापित करेंगे। यह बात मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को राजीव गांधी अन्तरराष्ट्रीय स्टेडियम में राष्ट्रीय खेल की तैयारियों की समीक्षा के दौरान कही।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि यह सुनिश्चित किया जाय कि खिलाड़ियों के लिए सभी सुविधाएं उच्च गुणवत्ता वाली और सुगम हों। नेशनल गेम्स के सफल आयोजन के लिए प्रत्येक विभाग से एक नोडल अधिकारी की तैनाती की जाए। खिलाड़ियों के रहने की व्यवस्था, खान-पान, परिवहन और आयोजन स्थल तक पहुंचने की सभी सुविधाओं का प्रबंधन और निगरानी की समुचित व्यवस्था की जाए। भोजन की गुणवत्ता और पौष्टिकता का विशेष ध्यान रखा जाए।

मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को निर्देश दिये कि राष्ट्रीय खेलों के बेहतर आयोजन के लिए सभी व्यवस्थाओं की प्रत्येक दिन समीक्षा की जाए। खेल मंत्री और स्वयं मुख्यमंत्री समय-समय पर राष्ट्रीय खेल के तैयारियों की समीक्षा करेंगें और विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि सभी स्पोर्ट्स उपकरण की खरीदते समय उनकी गुणवत्ता और मानकों का पूरा ध्यान रखा जाए। आयोजन स्थलों पर चिकित्सा सुविधाओं का पुख्ता इंतजाम किया जाए। खेलों के दौरान किसी भी आपातकालीन स्थिति का सामना करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जाए। आयोजन स्थलों पर सुरक्षा के दृष्टिगत सीसीटीवी कैमरों और सिक्योरिटी की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि आयोजन स्थलों पर पर्यावरण संरक्षण का विशेष ध्यान रखा जाए। प्लास्टिक के उपयोग को सीमित करने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं। उत्तराखण्ड में होने वाले राष्ट्रीय खेलों का आयोजन ग्रीन गेम्स की थीम पर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आयोजन स्थलों पर आने-जाने वाले आगुंतकों के लिए पेयजल एवं शौचालय की उचित व्यवस्था के साथ ही स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए। राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन के लिए सभी विभाग पूरे समन्वय से कार्य करें। इस आयोजन को सफल बनाने में जिलाधिकारियों की भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में होने वाले राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन के लिए प्रदेश की जनता का सहयोग भी लिया जायेगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि खेल आयोजन स्थलों पर सभी संबंधित विभाग अपनी जिम्मेदारी के साथ व्यवस्थाओं को बेहतर बनायेंगे। सड़क कनेक्टिविटी, स्वच्छता और खेलों के लिए सभी बेहतर व्यवस्थाओं पर उन्होंने विशेष बल दिया। राष्ट्रीय खेलों के दृष्टिगत फायर सेफ्टी ऑडिट के भी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये हैं।

भारतीय ओलंपिक संघ से 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए बनाई गई गेम्स टेक्निकल कंडक्ट कमेटी की अध्यक्ष सुनैना कुमारी ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों के लिए उत्तराखण्ड में तैयारियां बेहतर ढंग से हो रही हैं। अवस्थापना सुविधाओं का तेजी से विकास हो रहा है। कमेटी के सदस्य श्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि उत्तराखण्ड में इन्फ्रास्टक्चर के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा कार्य हुआ है। खेलों के आयोजन के लिए तैयारियां भी ठीक ढंग से चल रही हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से पहले हर स्टेडियम का ट्रायल होगा तो सभी खेल सफलतापूर्वक सम्पन्न हो सकेंगे। इस अवसर पर गुजरात एवं गोवा में आयोजित राष्ट्रीय खेलों के अनुभवों को भी वहां के अधिकारियों ने साझा किया। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने तीरंदाजी के खिलाडियों से भेंट की तथा स्वयं भी तीरंदाजी में प्रतिभाग कर खिलाडियों का उत्साह बढाया।

इस अवसर पर खेल मंत्री श्रीमती रेखा आर्या, विधायक श्री उमेश शर्मा काऊ, अवस्थापना अनुश्रवण परिषद् के उपाध्यक्ष श्री विश्वास डाबर, मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव श्री आर. के सुधांशु, श्री एल. फैनई, विशेष प्रमुख सचिव खेल श्री अमित सिन्हा, सचिवगण, विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष और वर्चुअल माध्यम से सभी जिलाधिकारी उपस्थित थे।

बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन

हरिद्वार । महानगर कांग्रेस ने देवपुरा चौक पर बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर बढ़ते अत्याचारों के विरोध में प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की विदेश नीति इसे रोकने में पूरी तरह विफल साबित हुई है। महानगर कांग्रेस अध्यक्ष अमन गर्ग और हरिद्वार ग्रामीण जिलाध्यक्ष राजीव चौधरी ने कहा कि भाजपा सरकार की विदेश नीति पूरी तरह विफल साबित हुई है।

इसके कारण बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद वहां पर अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ सरेआम लूटपाट एवं उनके धार्मिक स्थलों में आगजनी की घटनाएं हो रही है। जिसको रोकने में मोदी सरकार की विदेश नीति पूरी तरह विफल साबित हुई है। वरिष्ठ नेता संतोष चौहान और युवा नेता वरुण बालियान ने कहा कि भाजपा सरकार बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार पर हिंदुओं की रक्षा का दबाव बनाने में पूरी तरह असफल साबित हुई है। निवर्तमान पार्षद इसरार सलमानी और सुहैल कुरैशी ने कहा कि जहां एक तरफ प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1971 के भारत-पाक युद्ध में पाकिस्तान को करारा जवाब देकर बांग्लादेश की नींव रखी थी। वहीं, पूरे विश्व में डंका बजाने की बात कहने वाली भाजपा सरकार बांग्लादेश के हिंदू भाइयों की रक्षा के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही है। वरिष्ठ नेता सोम त्यागी, मनोज सैनी, निवर्तमान पार्षद राजीव भार्गव और कैलाश भट्ट ने कहा कि भाजपा सरकार की विदेश नीति कमजोर है और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए केंद्र सरकार को बांग्लादेश से राजनयिक संबंध तोड़ने जैसे कड़े कदम उठाने चाहिए। विरोध प्रदर्शन के दौरान महानगर कांग्रेस महासचिव तरुण व्यास, नगर अध्यक्ष ज्वालापुर अंकित चौहान, ब्लॉक अध्यक्ष विकास चंद्रा, विमल शर्मा साटू, दिनेश वालिया, महिला महानगर कांग्रेस अध्यक्ष लता जोशी, शशि झा, सुमन अग्रवाल, रचना शर्मा, चौधरी करतार सिंह खारी, मुकुल जोशी, अशोक गुप्ता, अजय गिरी, गौरव गोस्वामी, मोहित अरियाल, बलराम गिरी कड़क, आशीष शर्मा,विनोद गिरी, विक्की कोरी,अनंत पाण्डेय, अरूण राघव, रिषभ वशिष्ठ, विकास गुप्ता, हरजीत सिंह,एहसान अंसारी, सद्दीक गाड़ा, शोकत अली चीचू, निवर्तमान पार्षद उदयवीर सिंह चौहान, समर्थ अग्रवाल, मुकेश कुमार, धनीराम शर्मा, तरुण शर्मा, एश्वर्य पंत, तहसीन अंसारी आदि उपस्थित रहे।

विभाग की छापेमारी से हड़कंप, मेडिकल स्टोर बंद कर भागे संचालक

हरिद्वार । रावली मेहदूद ब्रह्मपुरी क्षेत्र में ड्रग्स विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने विभिन्न मेडिकल स्टोर पर छापेमारा। जिससे मेडिकल स्टोर संचालकों में हड़कंप मच गया। कई दवाई विक्रेता दुकाने बंद कर फरार हो गए। वहीं, अनियमितताएं मिलने पर ड्रग्स इंस्पेक्टर अनिता भारती ने चार मेडिकल स्टोर को बंद करा दिया है। पिछले कुछ दिनों से क्षेत्र में नियमों का उल्लंघन कर प्रतिबंधित दवाइयों की बिक्री और बच्चों के माध्यम से दवाइयां वितरित किए जाने की शिकायतें ड्रग्स विभाग को मिल रही थी। इस पर गुरुवार को ड्रग्स विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने सिडकुल थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुरी, रावली मेहदूद, बैरियर नंबर छह क्षेत्र में मेडिकल स्टोर पर दवाइयों की जांच की। ड्रग इंस्पेक्टर ने सभी मेडिकल स्टोर्स संचालकों को चेतावनी दी कि बिना लाइसेंस के दवा वितरण किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।

युवाओं को संस्कृति और परंपराओं का ज्ञान देना जरूरी

हरिद्वार । विश्व हिंदू परिषद उत्तराखंड के तत्वावधान में प्रांतीय मार्ग दर्शक मंडल की बैठक स्वामी नारायण मंदिर भूपतवाला में हुई। बैठक में श्री राम मंदिर तीर्थक्षेत्र अयोध्या और अंतरराष्ट्रीय उपाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद संत सम्मेलन की प्रस्तावना को संतों के समक्ष प्रस्तुत किया। वक्ताओं ने कहा कि युवाओं को अपनी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ना बहुत जरूरी है। बैठक की अध्यक्षता अखाड़ा परिषद के पूर्व प्रवक्ता बाबा हठयोगी ने की। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद प्रांतीय मार्गदर्शक मंडल की प्रस्तावना प्रस्तुत करते हुए श्रीराम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने कहा कि भारतीय समाज के पाश्चात्य संस्कृति को आत्मसात करने से हमारी पारंपरिक मूल्यों, रीति-रिवाजों और सांस्कृतिक विरासत को खतरा हो रहा है। भारतीय संस्कृति की विशेषता इसकी विविधता, सहिष्णुता और समृद्धि है। हमारी संस्कृति में विभिन्न मत पंथ संप्रदाय एवं संस्कृतियों के लोगों के बीच सामंजस्य और एकता की भावना है। हमें अपनी संस्कृति और परंपराओं के प्रति गर्व और सम्मान की भावना को बढ़ावा देना होगा। हमें युवाओं को संस्कृति और परंपराओं के विषय में शिक्षित करना होगा। ताकि वह अपनी संस्कृति को समझें और संस्कृति का सम्मान करें। भारत में संतों का विशेष प्रभाव ऐतिहासिक और सांस्कृतिक वास्तविकता है। संतों की वाणी और उनके द्वारा दिए गए संदेशों पर लोगों का विश्वास और समर्थन होना बेहद महत्वपूर्ण पहलू है। विश्व हिन्दू परिषद भी समाज महत्वपूर्ण योगदान करता है किंतु संत हिन्दू समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

सम्पादकीय

सियासी विवाद गरमाना लाजिमी

अमेरिका के न्याय मंत्रालय ने कहा है कि वहां सौर ऊर्जा संबंधी ठेके दिलवाने और उन परियोजनाओं में पैसा लगाने पर अमेरिकी निवेशकों को राजी करने के लिए अडानी ने भारतीय अधिकारियों को 25 करोड़ डॉलर की रिश्वत देने का वादा किया। उद्योगपति गौतम अडानी और उनके कारोबार पर अब बड़ा घेरा पड़ गया है। नया मामला हिंडनबर्ग रिपोर्ट जैसा नहीं है, क्योंकि इस बार अडानी और उनके उद्योग समूह से जुड़े कई प्रमुख लोगों पर अभियोग अमेरिका के न्याय मंत्रालय ने लगाया है। जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका में सौर ऊर्जा संबंधी ठेके दिलवाने और उन परियोजनाओं में पैसा लगाने पर अमेरिकी निवेशकों को राजी करने के लिए अडानी ने भारतीय अधिकारियों को 25 करोड़ डॉलर की रिश्वत देने का वादा किया। जिन पर अभियोग लगा है, उनमें गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और अडानी समूह की अक्षय ऊर्जा कंपनी के बड़े अधिकारी विनीत एस. जैन शामिल हैं। खबरों के मुताबिक अमेरिका की अदालत में पेश करने के लिए वहां के अधिकारी आरोपित व्यक्तियों के प्रत्यर्पण की मांग भारत सरकार से कर सकते हैं। भारत सरकार इस पर राजी होगी या नहीं- यह दीगर बात है। निर्विवाद रूप से ताजा घटना अडानी के लिए उससे कहीं बड़ा झटका है, जैसा पिछले साल उसे हिंडनबर्ग रिपोर्ट से लगा था। उस रिपोर्ट में इल्जाम लगाया गया था कि अडानी समूह ने अपने शेयरों के भाव को फर्जी ढंग से बढ़ाया और एकाउंटिंग में धोखाधड़ी की। ताजा खबर के ठीक पहले शेख हसीना सरकार के समय बांग्लादेश में अडानी को हुए बिजली परियोजना आवंटन की जांच के लिए विशेषज्ञों की समिति बनाने का समाचार आया था। यह भी चर्चा है कि श्रीलंका की नई सरकार वहां अडानी समूह को मिली परियोजना की समग्र जांच कराने पर विचार कर रही है। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में अडानी की परियोजनाओं पर भी हाल मे विवाद बढ़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डॉनल्ड ट्रंप के जीतते ही गौतम अडानी ने वहां दस बिलियन डॉलर के निवेश का एलान किया था। अब यह इरादा भी खटाई में पड़ सकता है। इन तमाम सूचनाओं से भारतीय शेयर बाजार को हिचकोले लगना और साथ ही देश में सियासी विवाद गरमाना लाजिमी है। उचित तो यह है कि कम-से-कम अब नरेंद्र मोदी सरकार अडानी विवाद की संसदीय जांच कराने पर राजी हो जाए।

पुलिस और जेल व्यवस्था

मुख्य मुद्दा यह है कि ये समस्या पैदा ही क्यों हुई है। स्पष्टतः इसकी जड़ें आपराधिक न्याय प्रक्रिया पर अमल से जुड़ी है। प्रश्न है कि क्या पुलिस और जेल व्यवस्था में बुनियादी सुधार के बिना कोई ठोस व्यावहारिक समाधान निकल सकता है?

एलान सचमुच बड़ा है। आशा है कि इसके पीछे इरादा भी नेक होगा। इसके बावजूद जिस भावना से घोषणा हुई है, उसके जमीन पर उतर सकने को लेकर कुछ सवाल मौजूद हैं।

एलान यह है कि ऐसे विचाराधीन कैदियों को रिहा किया जाएगा, जो अपनी संभावित सजा का एक तिहाई हिस्सा काट चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने धीमी न्याय प्रक्रिया से निपटने के लिए नई पहल की घोषणा की।

उन्होंने दो-टूक कहा कि छोटे अपराधों के आरोप में बंद ऐसे कैदियों को जमानत दी जाएगी, जिन्होंने अपनी संभावित सजा का एक-तिहाई हिस्सा काट लिया है।

इसके पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पिछले वर्ष संविधान दिवस पर अपने भाषण में जेलों में बढ़ती भीड़ की ओर ध्यान खींचा था। उन्होंने न्याय की ऊंची लागत की समस्या का जिक्र करते हुए शासन की तीनों शाखाओं- कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका- से इसका समाधान खोजने की अपील की थी। बहरहाल, कुछ व्यावहारिक सवाल हैं। मुख्य मुद्दा यह है कि ये समस्या पैदा ही क्यों हुई है। स्पष्टतः इसकी जड़ें आपराधिक न्याय प्रक्रिया पर अमल से जुड़ी है।

प्रश्न है कि क्या पुलिस और जेल व्यवस्था में बुनियादी सुधार के बिना कोई ठोस व्यावहारिक समाधान निकल सकता है? फिर मसले का संबंध न्यायपालिका से भी जुड़ता है। न्यायपालिका में जजों की भारी कमी और जमानत के मौजूदा धन-आधारित मॉडल का विकल्प ढूंढे बिना उपरोक्त नेक इरादे को अमली जामा पहना सकना कठिन हो सकता है। दरअसल, आधुनिक न्याय व्यवस्था में जैसाकि कहा जाता है, बेल नियम और जेल अपवाद होना चाहिए। यानी जमानत मिलना सभी मामलों में सामान्य नियम होना चाहिए। मगर कई ऐसे मामले हैं, जिनमें राजनीतिक मकसदों से व्यक्तियों पर गंभीर इल्जाम मढ़ दिए जाते हैं। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में यह चलन ज्यादा ही बढ़ गया है। ऐसे मामलों का क्या समाधान होगा? यानी समस्या का एक सूत्र सरकार के अपने नजरिए में भी है। कुल नतीजा जेलों में भारी भीड़ है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2024 की शुरुआत तक 1,34,799 लोग सुनवाई के इंतजार में जेलों में बंद थे, जिनमें से 11,448 पांच साल से ज्यादा समय से बिना सजा के जेल में हैं।

विकास लक्ष्यों को पर्यावरणीय उद्देश्यों के साथ जोड़ना अत्यन्त आवश्यक

-डॉ.सत्यवान सौरभ

हम पाते हैं कि सामाजिक लक्ष्यों का पीछा करना, आम तौर पर, उच्च पर्यावरणीय प्रभावों से जुड़ा होता है। हालाँकि, देशों के बीच बातचीत बहुत भिन्न होती है और विशिष्ट लक्ष्यों पर निर्भर करती है। दोनों ही बातचीत में, कार्बन भूमि और पानी की तुलना में छोटे बदलावों का अनुभव करता है। हालाँकि उच्च और निम्न आय समूहों द्वारा प्रयासों की आवश्यकता है, लेकिन अमीरों के पास मानवता के पदचिह्नों को कम करने का अधिक लाभ है। सामाजिक और पर्यावरणीय स्थिरता दोनों के महत्त्व को देखते हुए, यह महत्त्वपूर्ण है कि एसडीजी के बीच मात्रात्मक बातचीत को अच्छी तरह से समझा जाए ताकि जहाँ ज़रूरत हो, एकीकृत नीतियाँ विकसित की जा सकें। जलवायु परिवर्तन के प्रति भारत का सह-लाभ दृष्टिकोण विकास लक्ष्यों को पर्यावरणीय उद्देश्यों के साथ संरेखित करने का प्रयास करता है, जलवायु चुनौतियों का समाधान करते हुए सतत विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय लाभों को एकीकृत करके, इस रणनीति का उद्देश्य उत्सर्जन को कम करना और लचीलापन बढ़ाना है। उदाहरण के लिए, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना जैसी पहल इन प्राथमिकताओं को संतुलित करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। हम पाते हैं कि सामाजिक लक्ष्यों का पीछा करना, आम तौर पर, उच्च पर्यावरणीय प्रभावों से जुड़ा होता है। हालाँकि, देशों के बीच बातचीत बहुत भिन्न होती है और विशिष्ट लक्ष्यों पर निर्भर करती है। दोनों ही बातचीत में, कार्बन भूमि और पानी की तुलना में छोटे बदलावों का अनुभव करता है। हालाँकि उच्च और निम्न आय समूहों द्वारा प्रयासों की आवश्यकता है, लेकिन अमीरों के पास मानवता के पदचिह्नों को कम करने का अधिक लाभ है। सामाजिक और पर्यावरणीय स्थिरता दोनों के महत्त्व को देखते हुए, यह महत्त्वपूर्ण है कि एसडीजी के बीच मात्रात्मक बातचीत को अच्छी तरह से समझा जाए ताकि जहाँ ज़रूरत हो, एकीकृत नीतियाँ विकसित की जा सकें। भारत का सह-लाभ दृष्टिकोण, जो कई मोर्चों पर एक साथ प्रगति के लिए विकास लक्ष्यों को पर्यावरणीय उद्देश्यों के साथ जोड़ता है- भारत का सह-लाभ दृष्टिकोण सामाजिक और आर्थिक विकास को आगे बढ़ाते हुए जलवायु परिवर्तन को सम्बोधित करता है, जलवायु क्रियाओं को ग़रीबी में कमी और ऊर्जा पहुँच जैसे लक्ष्यों के साथ जोड़ता है। पीएम सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना न केवल अक्षय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देती है बल्कि कम आय वाले परिवारों को सस्ती बिजली भी प्रदान करती है। जलवायु क्रियाओं को विकास लक्ष्यों के साथ जोड़कर, सह-लाभ दृष्टिकोण पर्यावरणीय पहलों में सार्वजनिक समर्थन और भागीदारी को बढ़ाता है। पीएम ई-ड्राइव इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सब्सिडी प्रदान करता है, जिससे शहरी वायु प्रदूषण को सम्बोधित करते हुए उन्हें सुलभ बनाया जा सके और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम हो सके। जलवायु और विकास लक्ष्यों को एकीकृत करके, संसाधनों का अधिक कुशलता से उपयोग किया जाता है, जिससे नीति कार्यान्वयन में महत्त्वपूर्ण लागत बचत होती है। प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना उद्योगों को ऊर्जा दक्षता में सुधार करने, लागत कम करने और उत्सर्जन को कम करने में मदद करती है। यह दृष्टिकोण कृषि, जल संसाधन और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में लचीलापन बढ़ाने पर ज़ोर देता है, जो कमजोर आबादी के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजनाएँ क्षेत्र-विशिष्ट कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित करती हैं, ग्रामीण और तटीय क्षेत्रों के लिए लक्षित अनुकूलन रणनीतियों को सुनिश्चित करती हैं। सह-लाभ दृष्टिकोण जलवायु और विकासात्मक चुनौतियों दोनों को सम्बोधित करने वाली नवीन तकनीकों के विकास और तैनाती को प्रोत्साहित करता है। सौर ऊर्जा से चलने वाली सिंचाई प्रणालियों का विकास टिकाऊ कृषि का समर्थन करता है और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करता है। इन प्राथमिकताओं को संतुलित करने में इस रणनीति की प्रभावशीलता उत्सर्जन में कमी और आर्थिक विकास के दोहरे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बेहतर है। भारत ने आर्थिक विकास को बनाए रखते हुए अपनी उत्सर्जन तीव्रता को कम करने में प्रगति की है, जो सह-लाभ दृष्टिकोण की प्रभावशीलता को प्रदर्शित करता है। भारत ने पेरिस समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद की प्रति इकाई कार्बनडाई ऑक्साइड उत्सर्जन को लगातार कम किया है। यह रणनीति नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बदलाव को गति देते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा पहुँच की खाई को सफलतापूर्वक पाटती है। छतों पर सौर ऊर्जा पहलों ने दूरदराज के गांवों में बिजली पहुँचाई है, जिससे डीजल जनरेटर पर निर्भरता कम हुई है। भारत की रणनीति जलवायु क्रियाओं को निधि देने के लिए घरेलू पहलों पर केंद्रित है। इस आत्मनिर्भरता ने सकारात्मक परिणाम दिखाए हैं। भारतीय कार्बन बाज़ार उद्योगों में उत्सर्जन में कमी को प्रोत्साहित करने के लिए घरेलू संसाधनों को जुटाता है। जबकि यह दृष्टिकोण संधारणीय प्रथाओं को बढ़ावा देता है, लेकिन तेज़ आर्थिक विकास की आवश्यकता कभी-कभी पर्यावरण संरक्षण में समझौता करने की ओर ले जाती है। तत्काल ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिए कोयला आधारित बिजली संयंत्रों का विस्तार शुद्ध-शून्य लक्ष्यों को प्राप्त करने में चुनौतियाँ पेश करता है। राज्य कार्य योजनाओं के माध्यम से विकेंद्रीकृत जलवायु कार्यवाही यह सुनिश्चित करती है कि क्षेत्रीय चुनौतियों और अवसरों को पर्याप्त रूप से सम्बोधित किया जाए। अहमदाबाद जैसे शहरों में हीट एक्शन प्लान ने अत्यधिक गर्मी के प्रभावों को कम करने में मदद की है, जिससे कमज़ोर आबादी की रक्षा हुई है। जबकि सह-लाभ दृष्टिकोण पायलट कार्यक्रमों में प्रभावी रहा है, देश भर में इन पहलों को आगे बढ़ाना एक चुनौती बनी हुई है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना का लक्ष्य इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देना है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास अभी भी पिछड़ा हुआ है। भारत का सह-लाभ दृष्टिकोण जलवायु कार्यवाही को विकास के साथ प्रभावी ढंग से संतुलित करता है। यह स्थिरता और लचीलेपन को बढ़ावा देता है। अक्षय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और हरित बुनियादी ढांचे में निरंतर निवेश इस रणनीति को मज़बूत करेगा। यह स्थानीयकृत, प्रभावशाली समाधानों के माध्यम से वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के सिद्धांत को दर्शाता है, जो विकास और पर्यावरणीय लक्ष्य दोनों में सार्थक प्रगति को आगे बढ़ाता है।

डब्ल्यूएसी: विदेशी हितधारकों ने आयुर्वेद को चिकित्सा मान्यता दिलाने की बात कही

देहरादून । आयुर्वेद के कई देशों में व्यापक लोकप्रियता हासिल करने के साथ, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि अपने-अपने देशों में प्राचीन भारतीय चिकित्सा प्रणाली को मुख्यधारा में लाने के लक्ष्य की योजना पर चर्चा करने के लिए यहां 10वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस (डब्ल्यूएसी) में एकत्र हुए।

डब्ल्यूएसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि सभा (आईडीए) में विचार प्रस्तुत करते हुए, प्रतिभागियों ने आयुर्वेद को वैश्विक समर्थन देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की और इसे पूरक या वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली के रूप में व्यापक मान्यता दिलाने के लिए सरकारों के बीच अधिक बातचीत करने का आह्वान किया। लगभग 300 प्रतिनिधियों ने विभिन्न देशों से आईडीए में भाग लिया। ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, पुर्तगाल, पोलैंड, अर्जेंटीना और ब्राजील के प्रतिनिधियों ने अपने देशों में आयुर्वेद की बढ़ती मांग पर प्रकाश डाला, जहां इसे वर्तमान में केवल जीवनशैली या कल्याण प्रणाली के रूप में पेश किया जा सकता है। उन्होंने आयुर्वेद के विकास में नियामक और अन्य बाधाओं के बारे में विस्तार से बताया और सुझाव दिया कि सरकार और विश्व आयुर्वेद फाउंडेशन (डब्ल्यूएसी के आयोजक) उन्हें दूर करने में कैसे मदद कर सकते हैं।

आईडीए का उद्घाटन करते हुए, केंद्रीय आयुष सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने कहा कि उनका मंत्रालय दुनिया भर में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के सभी प्रयासों का समर्थन और सहयोग करता है। उन्होंने कहा कि पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों की वैश्विक रूपरेखा को बढ़ाने के लिए 250 मिलियन डॉलर के निवेश के साथ 2022 में गुजरात के जामनगर में डब्ल्यूएचओ ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर (जीटीएमसी) की स्थापना की गई थी। उन्होंने दुनिया भर के आयुर्वेद हितधारकों से जीटीएमसी और आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर मुद्दों और चिंताओं का समाधान करने का आग्रह किया। वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी में एनआईसीएम हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट के डॉ. दिलीप घोष ने कहा कि आयुर्वेद सिर्फ 19 करोड़ की आबादी वाले देश ऑस्ट्रेलिया में 6.2 बिलियन डॉलर का कारोबार करता है। यह वृद्धि मीडिया के कुछ वर्गों द्वारा आयुर्वेद के प्रति तीव्र पैरवी को आकर्षित करना जारी रखती है, खासकर जब यूरोप में कुछ आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों पर हाल ही में प्रतिबंध जैसी नकारात्मक रिपोर्टें प्राप्त होती हैं।

विश्व योग और आयुर्वेद आंदोलन के अध्यक्ष डॉ. जोस रूग ने कहा, ब्राजील में, आयुर्वेद के 4,000 चिकित्सक हैं और कानून उन्हें ष्चिकित्सकष् मानता है। वह दक्षिण अमेरिकी देश में 'शुद्ध सबा योग' और आयुर्वेद आश्रम से जुड़े हैं। रियो डी जेनेरो में तीन आयुर्वेदिक केंद्र हैं, जो सीमित शोध कर रहे हैं, और बढ़ती मांग को देखते हुए ऐसे और केंद्रों की संभावना है। डॉ. हर्षा ग्रामिंगर जो यूरोपीय संघ के देश में आयुर्वेद उपचार और उत्पाद लाने में अग्रणी हैं, ने कहा कि हालांकि, जर्मनी में आयुर्वेद का दृश्य बिल्कुल अलग था। वह एक ऐसे अस्पताल में काम करती हैं जो आयुर्वेद और एलोपैथी दोनों के साथ एकीकृत उपचार प्रदान करता है। उन्होंने कहा हमारे पास बहुत अच्छे शैक्षणिक संस्थान हैं और हमने (आयुर्वेद में) बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। मैं हर अस्पताल में आयुर्वेद देखना चाहूंगी, जहां सिर्फ खाद्य उत्पाद ही नहीं, बल्कि दवाएं भी उपलब्ध हों।

नेपाल और श्रीलंका के प्रतिनिधि अपने देशों में आयुर्वेद के विकास से खुश थे। श्रीलंका के स्वास्थ्य मंत्रालय में सलाहकार डॉ. एमजी सजीवानी ने बताया कि आयुर्वेद डिग्री कोर्स कराने वाले छह विश्वविद्यालय संबद्ध संस्थान हैं। नेपाल के स्वास्थ्य और जनसंख्या मंत्रालय में आयुर्वेद और वैकल्पिक चिकित्सा के प्रमुख डॉ. पुष्प राज पौडेल ने बताया कि 'हिमालयन' देश में दक्षिण एशिया की सबसे पुरानी फार्मेसी है, जो तीन शताब्दियों पुरानी है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवा प्रणाली अच्छी तरह से विकसित है और समाज द्वारा व्यापक रूप से स्वीकार की जाती है। इस सत्र में डॉ. विधु शर्मा और एन व्लास (ऑस्ट्रेलिया), डॉ. शिल्पा स्वर (सिंगापुर), डॉ. किम सोक जियोंग (दक्षिण कोरिया), डॉ. शिवानी सूद (पोलैंड), डॉ. गैब्रिएला पलेटा (पुर्तगाल) और डी जॉर्ज बेरा (अर्जेंटीना) भी शामिल हुए।

वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस के प्लेनेटरी सेशन में विषय-विशेषज्ञों ने साझा किए बहुमूल्य अनुभव

देहरादून । प्लेनेटरी सेशन में न्यू एज संहिता विषय पर पैनलिस्ट उपेंद्र दीक्षित (गोवा) अभिजीत सराफ (नासिक) और प्रसाद बावडेकर (पुणे) ने अपने विचार रखे। आयुर्वेद के क्षेत्र में अधिक लोगों को कैसे जोड़ा जाए, इसमें अधिक शोध और अनुसंधान को कैसे बढ़ावा मिले तथा आयुष चिकित्सा को आम जनमानस के बीच कैसे लोकप्रिय बनाया जाए। बताया कि आयुर्वेद के क्षेत्र में जितने भी नए रिसर्च हो रहे हैं और नई रचनाएं लिखी जा रही हैं उसकी भाषा बहुत ही सरल हो और डिजिटल एप (कोड) के अंतर्गत अधिक-से-अधिक स्थानीय भाषा में उसकी उपलब्धता हो ताकि देश-विदेश का हर एक नागरिक अपनी सुगम भाषा में उसकी आसानी से स्टडी कर सके। आयुर्वेद आहार विषय पर केंद्रित व्याख्यान में पैनलिस्ट ने बताया कि शरीर की प्रकृति (कफ, वात, पित) के अनुरूप आहार होना चाहिए। फूड इज मेडिसिन, बट मेडिसिन इज नॉट फूड के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। इसमें सुझाव आया कि एफ. एस.एस.आई (भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण) खाद्य पदार्थों के सर्टिफिकेशन में आयुर्वेद आहार के मानक को भी सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया में शामिल करें। एविडेंस बेस्ड आयुर्वेद थीम पर आधारित व्याख्यान में पैनलिस्ट ने बताया कि आयुर्वेद के क्षेत्र में नित्य होने वाले नए शोध,अनुसंधान एवं व्यवहारिक ज्ञान को प्यूरिफाई करने के लिए एक मानक संस्था होनी चाहिए, जिससे जनमानस तक पहुंचने से पूर्व ज्ञान,जानकारी व तकनीक को कई चरणों में जांचा-परखा जा सके।

आयुर्वेद की परंपरागत जानकारी रखने वाले वैद्य की गोष्ठी में देशभर से आए वैद्य ने उनके सामने आने वाली विभिन्न समस्याओं और सुझावों को साझा किया। उन्होंने कहा कि जड़ी बूटी उत्पादन से लेकर उसकी फूड प्रोसेसिंग, मार्केटिंग और विक्रय तक लागत बहुत आती है जबकि उसके अनुरूप मुनाफा नहीं मिल पाता। उन्होंने सुझाव दिया कि परंपरागत वैध की जानकारी रखने वाले लोगों को प्रमाण पत्र देकर उनका प्रमाणीकरण किया जाए। साथ ही परंपरागत ज्ञान को हर एक नागरिक तक पहुंचाने के लिए गांव-गांव तक आयुर्वेद स्कूलों की स्थापना की जाए। राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग कॉन्क्लेव में देश भर के लगभग 200 से अधिक आयुर्वेदिक चिकित्सकों ने प्रतिभा किया। इसमें आयुर्वेदिक चिकित्सकों के सेवा के अवसरों, दायित्व और अधिकारों पर विस्तृत चर्चा की गई। आयुष चिकित्सा लाभ के लिए आने वाले विदेशी पर्यटकों को कैसे बेहतर सुविधा दी जा सकती है इस संबंध में प्रधानमंत्री द्वारा लांच की गई आयुष वीजा सेवा से संबंधित जानकारी भी साझा की गई।

उत्तराखण्ड में बर्फबारी के बाद शीत लहर का कहर जारी

चारोधाम में तापमान माइनस में पहुंचा

देहरादून । उत्तराखंड में रविवार और सोमवार को जोरदार बर्फबारी हुई थी। तब तापमान काफी गिरने से कड़ाके की ठंड पड़ने लगी थी। शीत लहर चलने लगी थी। मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को अच्छी धूप निकली। इसके बाद तापमान थोड़ा संभला है। आज चार धामों में सिर्फ बदरीनाथ धाम के ही दोनों तापमान माइनस में हैं। बाकी तीन धामों के तापमान माइनस से ऊपर आ गए हैं। चमोली जिले में स्थित बदरीनाथ धाम सबसे ठंडा बना हुआ है। यहां दोनों तापमान माइनस में चल रहे हैं। बदरीनाथ धाम का अधिकतम तापमान-3 डिग्री सेल्सियस है तो न्यूनतम तापमान भी -13 डिग्री है। इस कारण यहां कड़ाके की ठंड है। धाम के आसपास के झरने और झीलें जम गई हैं। भगवान शिव के केदारनाथ धाम में तीन दिन अच्छी धूप निकलने से अधिकतम तापमान थोड़ा सुधरा है और माइनस से बाहर निकल आया है। केदारनाथ धाम का अधिकतम तापमान 1डिग्री सेल्सियस है तो न्यूनतम तापमान -11 डिग्री सेल्सियस है। सुबह-शाम कड़ाके की ठंड है। दिन में मौसम ठीक है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री धाम में न्यूनतम तापमान तो माइनस में है, लेकिन अधिकतम तापमान अब माइनस से बाहर आ गया है। गंगोत्री धाम का अधिकतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस है तो न्यूनतम तापमान-8 डिग्री सेल्सियस है। यानी बर्फ जमने से भी 8 डिग्री सेल्सियस नीचे। उत्तरकाशी जिले में स्थित यमुनोत्री धाम का अधिकतम तापमान फ्रीजिंग प्वाइंट पर है। आज यमुनोत्री का अधिकतम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो न्यूनतम तापमान-9 डिग्री सेल्सियस है। दो दिन पहले यमुनोत्री के दोनों तापमान माइनस में चल रहे थे। पिछले तीन दिन की कड़ी धूप ने तापमान में इतना बदलाव ला दिया है।

उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों में विंटर टूरिज्म के लिए शानदार मौसम है। पहाड़ों की रानी मसूरी में इस समय अधिकतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान-2 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। सोमवार को मसूरी में भी बर्फबारी हुई थी। इससे यहां पर्यटकों की भीड़ उमड़ पड़ी। तीन दिन धूप पड़ी तो अधिकतम तापमान थोड़ा चढ़ गया लेकिन न्यूनतम तापमान अभी माइनस में ही है। सरोवर नगरी नैनीताल में घूमने के लिए बहुत बढ़िया मौसम है। यहां भी बर्फ पड़ चुकी है। नैनीताल का अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस है। ऐसे में फिर कभी भी सरोवर नगरी में बर्फ पड़ सकती है। अल्मोड़ा जिले के रानीखेत का तापमान मिलाजुला है। दिन में धूप पड़ रही है तो रानीखेत का अधिकतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस है। सुबह-शाम और रात में कड़ाके की ठंड के कारण न्यूनतम तापमान फ्रीजिंग प्वाइंट से भी नीचे-2 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। नैनीताल जिले के पर्यटक स्थल मुक्तेश्वर में सर्दियों के पर्यटन का आनंद लेने लायक मौसम है। मुक्तेश्वर का अधिकतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस है तो न्यूनतम तापमान-1 डिग्री सेल्सियस है। जौनसार बावर इलाके में स्थित चकराता में बर्फबारी के बाद से ठंड बनी हुई है। चकराता का अधिकतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस है तो न्यूनतम तापमान-2 डिग्री सेल्सियस है। अगर आप मैदानी इलाकों के प्रदूषण से परेशान हैं, काम के बोझ से थक गए हैं तो उत्तराखंड के ये पर्यटन स्थल आपको रिफ्रेश कर देंगे। तो फिर उठाइए बैग और उसमें सर्दियों वाले कपड़े डालकर पहुंच जाइए उत्तराखंड।

राष्ट्रीय खेलों में चयन होने पर खिलाड़ियों का स्वागत किया

रुड़की । कक्षा नौ के छात्र वासु छावड़ी ने प्रदेश में कब्बडी, खो खो और कूद प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया है। छात्र का चयन राष्ट्रीय स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं के लिए होने पर शिक्षकों और अभिभावकों ने उसे शुभकामनाएं दी है। शिक्खर निवासी वासु छावड़ी लंढौरा के प्राइवेट स्कूल में कक्षा नौ में पढ़ता है। छात्र ने हाल ही में उत्तराखंड खेल महाकुंभ 2024 की खेल प्रतियोगिता में भाग लिया था। छात्र वासु ने अंडर 17 आयू वर्ग में प्रदेश स्तर पर कबड्डी, खो खो और कूद प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया है। इसी स्कूल की कक्षा चार की छात्रा सोनाक्षी ने प्रदेश स्तर पर योगा में द्वितीय स्थान हासिल किया है। प्रधानाचार्य आयुष जैन ने बताया कि छात्र वासु राष्ट्रीय स्तर पर कलकत्ता में आयोजित होने वाली खेल प्रतियोगिताओं में खेलेगा। छात्र छात्रा की इस उपलब्धि पर स्कूल के अध्यापकों ने बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए उनका स्वागत किया। छात्र वासु के अभिभावक पंकज छावड़ी, सविता छावड़ी, हरवीर और कनिष्का ने बताया की वासु को बचपन से कबड्डी का शौक रहा है।

कांग्रेस को ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए

शकील अख्तर

महाराष्ट्र में भाजपा की अविश्वसनीय स्ट्राइक रेट। और ईवीएम पर सवाल तेज हुआ तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सवाल की शक्ल में आ जाता है कि जीतने पर चुप हार गए तो ईवीएम पर सवाल? नरेटिव सेट कर दिया।ज

ऐसे कहा जा रहा है जैसे विपक्ष कोर्ट में गया हो। यह एक पुरानी टेक्टिस हैज् किसी आदमी से इस तरह की पीआईएल दाखिल करवा दो। और उसके बाद कहो कि सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष को करारा जवाब दिया। जो बात बीजेपी और मोदी सरकार कहती है वही चुनाव आयोग कहता है, फिर वही बात सुप्रीम कोर्ट से आती है ।

विपक्ष का मुख्य मुद्दा नरेंद्र मोदी को हटाना है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने सभी संस्थाओं पर ऐसा कब्जा कर लिया है कि सिवाए विपक्ष के कोई आवाज बची ही नहीं है। और विपक्ष जिसमें कांग्रेस बड़ी पार्टी है उसके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी का यह कहना सही है कि हमारा माइक ही बंद कर दिया जाता है। मगर उससे ज्यादा यह कहना बहुत महत्वपूर्ण, दमदार और उत्साहवर्धक है कि माइक बंद कर दो मगर मैं खड़ा रहूंगा। नेता प्रतिपक्ष कहते हैं कि मुझसे कहा जाता है कि माइक बंद हो गया तो बैठ जाओ। मगर मैं बैठूंगा नहीं। खड़ा रहूंगा।

तो एक आवाज जो विपक्ष की बची है उसे भी बंद करने की कोशिश है। लेकिन यही एक काम सबसे मुश्किल है। विपक्ष के तमाम नेता एक मजबूत ताकत के रूप में खड़े हुए हैं। राहुल ने यही कहा बैठेंगे नहीं। खड़े रहेंगे। लड़ते रहेंगे। और जाहिर है तब तक जब तक कि लोकतंत्र अपनी मूल भावना के अनुरूप वापस नहीं आ जाता।

और जैसा कि हमारा पहला वाक्य स्पष्ट है कि ऐसा प्रधानमंत्री मोदी को हटाए बिना नहीं हो सकता। सबसे बड़ा इंस्टिट्यूशन तो

न्यायपालिका था। लेकिन अभी रिटायर हुए और नई पोस्टिंग की राह देख रहे चीफ जस्टिस चन्द्रचुड़ ने क्या कहा? हम विपक्ष नहीं! क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ऐसे समझिए जैसे सरकार कहे कि हमने कोई जनता का ठेका नहीं ले रखा है। अभी नहीं कहा। मगर यही हालत रही तो जल्दी ही डायरेक्ट यह कह दिया जाएगा कि क्या तुम्हारी गरीबी, बेरोजगारी हमारी जिम्मेदारी है? बस यह कहने के लिए चुनाव में जाने की मजबूरी ना हो।

हालांकि सब कुछ सेट है। मगर फिर भी चुनाव में जाना पड़ता है। इसलिए जनता पर अप्रत्यक्ष रूप से सब कुछ डाला जाता है। उसके अधिकारो की बात न करके केवल कर्तव्य याद दिलाए जाते हैं। मगर डायरेक्ट अभी यह कहने की स्थिति नहीं है कि आप कौन?

इसलिए वह स्थिति आए उससे पहले देश में वापस लोकतंत्र को चाहने वालों को मोदी को हटाना पड़ेगा। और मोदी को हटाने के लिए ईवीएम को हटाना पड़ेगा। इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने संविधान दिवस पर बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। वोट ईवीएम से नहीं। अगर कांग्रेस यह आन्दोलन सारे विपक्षी दलों को विश्वास में लेकर सही तैयारी से करती है तो समझ लीजिए की ईवीएम हटते ही मोदी भी हट गए। कांग्रेसी भी, दूसरे भी मोदी सरकार की जान बताते हैं कि इस तोते में है। मगर सही यह है कि जान ईवीएम में है।

कैसे? इसका एक उदाहरण बताते हैं। महाराष्ट्र के अविश्वसनीय स्ट्राइक रेट। भाजपा के 90 प्रतिशत के बाद ईवीएम पर सवाल तेज हो गए। और सवाल होते ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सवाल की शक्ल में आ जाता है कि जीतने पर चुप हार गए तो ईवीएम पर सवाल? नरेटिव सेट कर दिया। मीडिया इसी पर लगा हुआ है। और गोदी मीडिया के बाद दूसरा बड़ा प्रचार उपकरण व्ह्टस् एप भी। विपक्ष के हारने का बहाना ईवीएम!

ऐसे कहा जा रहा है जैसे विपक्ष कोर्ट में गया हो। यह एक पुरानी टेक्टिस है जिसे विपक्ष उजागर नहीं कर पाता कि कोई भी गंभीर मामला होने पर किसी भी गैर गंभीर या अपने किसी आदमी से इस तरह की पीआईएल दाखिल करवा दो। और उसके बाद कहो कि सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष को करारा जवाब दिया। जो बात चुनाव आयोग कहता है, बीजेपी और मोदी सरकार कहती है वही बात जब सुप्रीम कोर्ट से आती है तो जनता फिर सोचने लगती है कि मैंने ही बेरोजगारी, मंहगाई के खिलाफ वोट दिया था दूसरों ने नहीं। अब मेरे अकेले वोट से क्या होता है? मोदी जी यही चाहते हैं। उनके विरोध की आवाज निराश हो जाए।

अब जरा यह देखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता को पूरा मौका दिया गया कि वह अपनी बात कहे। और उसने बताया कि वह तीन लाख अनाथ बच्चों को बचा चुका है। 40 लाख विधावाओं की उसने मदद की है। 155 देशों की यात्राएं। 180 पूर्व आईएएस, आईपीएस, न्यायधीश उसकी याचिका के साथ है। और 18 राजनीतिक दल भी।

कोर्ट में वह खुद ही अपनी पैरवी कर रहा था। और माननीय न्यायधीश उससे और सवाल पूछ पूछकर उसे खूब आत्म प्रचार का मौका दे रहे थे। याचिकाकर्ता था डाक्टर ए के पाल और सुप्रीम कोर्ट की बैंच थी न्यायधीश विक्रम नाथ और पीवी वराले की। क्या मतलब था पाल की बातों का? मगर फैसला आ गया। माहौल बन गया। और यह कोई एक अकेला मामला नहीं है। ऐसे ही कई बड़े मुद्दों पर जानबुझकर अपने लोगों से याचिका दाखिल करवाकर उस मुद्दे को कमजोर कर दिया जाता है। और मनचाहा नरेटिव (कहानियां) बना लिया जाता है। कांग्रेस को और विपक्ष को यह भी ध्यान रखना चाहिए और तत्काल बात स्पष्ट करना चाहिए। साथ ही यह समझना चाहिए कि ईवीएम पर यह याचिका क्यों दाखिल की गई। इसीलिए कि उन्हें मालूम है कि ईवीएम ही एक ऐसा मुद्दा है जो अगर ठीक वही जनादेश देने लगे जो मतदाता ने उसमें फीड किया है तो फिर उनका इस तरह चुनाव जीतना मुश्किल है। जैसा कि हमने उपर कहा कि हर संस्थान पर कब्जा कर लिया है। और चुनाव आयोग जैसे इन्स्टिट्यूशन तो बिल्कुल सरकार की भाषा बोलने लगे हैं। विपक्ष को गैर जिम्मेदार और आदतन हमला करने वाला तक बता दिया। इसलिए अब पूरी चुनाव प्रणाली ही शक के घेरे में आ गई है। वोटर लिस्ट में नाम काटने और जाली नाम चढ़ाने के आरोपों के बाद यह गंभीर आरोप भी है कि मतदाता सूची फाइनल होने से पहले उसका एक्सेस (पहुंच) भाजपा के पास होता है। वह अपनी मर्जी से नाम काटती और जोड़ती है। अभी कांग्रेस ने महाराष्ट्र के मामले में यह आरोप लगाया।

तो मतदाता सूची से लेकर नतीजों की घोषणा रोक लेने तक हर जगह धांधली के आरोप हैं। मगर उल्टा चुनाव आयोग विपक्ष को चेतावनी देती है कि भविष्य में ऐसे आरोप नहीं लगाएं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने ईवीएम को मैनेज कर लेने की बात पहले नहीं समझी थी। 2018 में जब राहुल खुद कांग्रेस अध्यक्ष थे पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली के इन्दिरा गांधी ओपन स्टेडियम में हुआ था। वहां बाकायदा ईवीएम के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया। मगर उस पर कोई अमल नहीं किया गया।

29 नवम्बर को कांग्रेस की सर्वोच्च नीति निर्धारण इकाई सीअब्ल्यूसी की मीटिंग हुई। उसमें आन्दोलन पर विचार होगा। कांग्रेसियों को इससे बहुत उम्मीद है। पिछले कुछ समय से कांग्रेस जिस तरह सडक़ पर संघर्ष कर रही है उसने मोदी को हिलाया तो है। लोग कहते हैं कांग्रेस सडक़ पर क्यों नहीं आती। यह भी एक नरेटिव (झूठी धारणा) है। राहुल ने दो यात्राएं कीं। पहली तो चार हजार किलोमीटर पैदल। कन्याकुमारी से कश्मीर तक। दूसरी साढ़े छह हजार किलोमीटर से उपर। यह सब कहां कीं? सडक़ पर नहीं थीं? हवा में उड़ते हुए जा रहे थे? बोल देते हैं चाहे जो! कांग्रेस को सडक़ पर उतरना चाहिए। राहुल से ज्यादा देश में किसी ने

यात्राएं नहीं की। दस हजार किलो मीटर से उपर। इन यात्राओं ने माहौल बदला। ईवीएम के बावजूद मोदी लोकसभा में बहुमत नहीं पा पाए। चन्द्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार के सहारे सरकार बनाना पड़ी। लेकिन यह भी कहना पड़ेगा कि हरियाणा की अप्रत्याशित हार ने राहुल की बनाई सारी बढ़त को खत्म कर दिया। हरियाणा की निम्नतम स्तर पर की गई गुटबाजी कांग्रेस को बहुत महंगी पड़ी। कांग्रेस को ईवीएम के खिलाफ तो आंदोलन करना चाहिए। वह एक बड़ा कारण है। मगर उसका बहाना बनाकर गुटबाज नेता मुझे मुख्यमंत्री बना दो, मुझे भी बना दो के अपने स्वार्थी और पार्टी विरोधी आचरण से मुक्त नहीं हो सकते। लड़ाई बहुकोणीय है। ईवीएम के साथ अपने अंदर के उन सारे क्षत्रपों को बाहर फेंकने की जिन्हें अपने निज स्वार्थ के आगे कुछ नहीं दिखता है। कांग्रेस को कम से कम दो राज्यों में जहां सबसे ज्यादा गुटबाजी रही और हार का प्रमुख कारण भी राजस्थान और हरियाणा वहां तो कड़ाई करना ही पड़ेगी। तभी ईवीएम के खिलाफ उसकी लड़ाई की विश्वसनीयता बढ़ेगी।

धनपति का एजेंट बन धंधे दिलाने का राजधर्म

हरिशंकर व्यास

याद करें भारत में कौन सा राजा (सम्राट अशोक से लेकर पृथ्वीराज चौहान या मुस्लिम-अंग्रेज शासकों के कार्यकाल में), प्रधानमंत्री ऐसा हुआ, जिसने किसी उद्योगपति-व्यापारी की पैरोकारी को अपना राजधर्म बनाया? जवाब है कि ऐसा उदाहरण प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल के किसी भी राजा, प्रधानमंत्री का नहीं है। क्यों? इसलिए क्योंकि राजनीति का उद्देश्य व कर्तव्य समाज के सभी वर्गों में संतुलन बनाने का है। राजा-प्रधानमंत्री कितना ही भ्रष्ट हुआ हो उसने किसी पर मेहरबान हो कर उसे लाइसेंस, कोटा दे कर क्रोनी पूंजीपति बनाया हो लेकिन राजा खुद धनपति का एजेंट बन कर उसे काम धंधे दिलाने को राजधर्म बनाए ऐसा एक भी उदाहरण भारत के इतिहास में नहीं है! आखिर राजा, राजा होता है, उसकी गरिमा पूरी नस्ल, कौम और देश की आन-बान-शान का प्रतीक होती है! चीन, रूस, अमेरिका, जापान आदि तमाम देशों की सरकारें देश की समृद्धि, व्यापार, वाणिज्य के लिए कूटनीति करती हैं, करार करती हैं, शी जिनफिंग, पुतिन जैसे तानाशाह शासक क्रोनी पूंजीपतियों का खेला भी बनाते हैं लेकिन क्या कभी सुना कि इनमें से किसी ने किसी चाइनीज या रूसी उद्योगपति की पैरोकारी को अपना राजधर्म बनाया है? अमेरिका घोषित पूंजीवादी देश है लेकिन उसका प्राथमिक धर्म सबको बराबर के अवसर मुहैया कराने का है। पूरी दुनिया में अमेरिकी कंपनियों का दबदबा और धंधा है लेकिन कंपनियां, अमेरिकी खरबपति अपने बूते, अपनी तकनीक, अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस, अपनी उद्यमशीलता और कॉरपोरेट कायदों-नियमों से बने हुए हैं। सच्ची प्रतिस्पर्धा में बिजनेस करते हैं। डोनाल?ड ट्रंप ने पिछले कार्यकाल में अमेरिकी मोटरसाइकिल कंपनी हार्ले-डेविडसन को ले कर भारत पर दबाव बनाया था तो उसका आधार भारत-अमेरिकी व्यापार नीति में कस्टम ड्यूटी की असमानताओं के हवाले था न कि उस कंपनी की निज पैरोकारी थी। शी जिनफिंग हों या पुतिन, इनके इतने वर्षों के शासन में वहां के किसी भी एक ऐसे उद्योगपति का नाम नहीं है, जैसे भारत में नरेंद्र मोदी से गौतम अडानी का बना है! जिन कंपनियों और उद्योगपतियों को लेकर चर्चा थी कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से फलां-फलां की किस्मत बनी उनमें एक भी शी जिनफिंग या पुतिन के माई बाप उद्योगपति के रूप में दुनिया में चर्चित नहीं है! उलटे कभी जो ऐसे नाम सुने भी गए वे या तो जेल में (हां, चाइनीज खरबपति) है या गुमनामी में चले गए हैं! क्यों? इसलिए क्योंकि राजा, राजा होता है वह कैसे भला किसी सेठ को अपनी व्यवस्था, शासन, राजधर्म का पर्याय बनने दे सकता है। मगर भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गौतम अडानी को अपने राजधर्म में, जब तक सूरज-चांद रहेगा तब तक अडानी का राज चलेगा वाली जो परिघटना रची है वह विश्व के इतिहास में अनहोनी है। और यह भारत का वैश्विक कलंक है! अमेरिका, यूरोप और वैश्विक वित्तीय जगत में अडानी ग्रुप की आज बदनामी का सत्य अपनी जगह है लेकिन क्या विश्वास करेंगे कि अफ्रीका के केन्या में भारत को लेकर क्या नैरेटिव बना हुआ है? बतौर भारतीय मेरे और आपके, 140 करोड़ लोगों के वजूद में केन्या में सुनाई दिए इस वाक्य पर जरा गौर करें- भ्रष्ट भारतीय आखरिक़ार यहां आ ही गए। मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि ये सब हो रहा है। हमारे राष्ट्रपति जो केन्या से बहुत मोहब्बत करते हैं, उन्होंने 30 साल के लिए एयरपोर्ट अडानी को दे दिया है। अडानी सुन लीजिए अगर 2027 में हम राष्ट्रपति चुने गए तो आपको यहां से भागना होगा। हम भ्रष्टाचार से नफरत करते हैं, इसलिए आपसे भी नफरत करते हैं। उफ! यह भावना। तभी केन्या के राष्ट्रपति ने जब संसद में अडानी के ठेके को रद्द करने की घोषणा की तो सारे सांसदों ने खड़े हो कर ऐसे तालियां बजाई मानों कोई ऐतिहासिक काम हुआ हो, भ्रष्टाचार से आजादी मिली हो!

मौसम बदलने से हो रहा है गले में इंफेक्शन और जुकाम

अक्टूबर आते ही मौसम बदलने लगा है. थोड़े-थोड़े ठंड का भी एहसास हो रहा है. दिन में थोड़ी गर्मी लेकिन रात में ठंड लग रही है. ऐसे में गले में इंफेक्शन और जुकाम जैसी छोटी-छोटी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. हालांकि, इनसे बचने के लिए कुछ घरेलू उपाय कर सकते हैं.

सर्दी-जुकाम या गले में खराश-इंफेक्शन से बचने के लिए शहद रामबाण साबित हो सकता है. शहद में कुछ चीजें मिलाकर खाने से इस तरह की प्रॉब्लम्स से छुटकारा मिल सकता है. शरीर की इम्यूनिटी भी बढ़ती है और कई बीमारियां दूर ही रहती हैं.

शहद में अदरक मिलाकर खाएं

गले में इंफेक्शन और जुकाम के लिए शहद और लहसुन चमत्कारिक है. बच्चे हों या बड़े शहद में लिपटी लहसुन की एक कली हर दिन खाने से इससे जल्दी आराम मिल जाएगा. लहसुन में एलिसिन पाया जाता है, जो ब्लड शुगर घटाने, कोलेस्ट्रॉल कम करने और इंफेक्शन से लडने़ में मदद करता है. लहसुन-शहद दोनों एंटी ऑक्सीडेंट्स से भरपूर हैं. इससे इम्यूनिटी सिस्टम भी मजबूत होता है.

शहद और मुलेठी

मुलेठी के छोटे टुकड़े चूसने से गले की खराश, इंफेक्शन, जुकाम और खांसी ठीक हो जाती है. मुलेठी में एंटी-ऑक्सिडेंट्स और एंटीबायोटिक गुण होते हैं, जो कई बीमारियों से बचाते हैं. इससे अर्थराइटिस, दर्द सूजन को कम करने में भी मदद मिलती है. मुलेठी में मैग्नीशियम, कैल्शियम और बीटा कैराटीन जैसे मिनरल्स और फ्लेवोनॉइड्स भी होते हैं, जो इसे ज्यादा ताकतवर बनाते हैं. इसे शहद के साथ मिलाकर खाने से शरीर को काफी फायदे होते हैं. एक चम्मच मुलेठी के पाउडर में शहद मिलकार दिन में दो बार खाने से मौसमी बीमारियों से राहत मिलती है.

इन चीजों से भी गले की दिक्कत होगी दूर

गले में राहत देने के लिए तुलसी की पत्तियां भी कमाल की होती हैं. अगर सर्दी में आपके गले में दर्द रहता है या फिर किसी भी तरीके के संक्रमण से बोलने में भी दिक्कत हो रही है तो तुलसी के पत्ते को खाने से ये दिक्कत दूर हो जाएगी, क्योंकि तुलसी के पत्तों में एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं, जो खाने से गले में काफी राहत पहुंचाने का काम करेगें. इन पत्तियों को आप कच्चा या फिर पानी में उबालकर भी खा सकते हैं. इसके अलावा गले में दिक्कत होने पर आप अदरक को चबाकर खाएंगे तो ये भी आपके लिए कारगर साबित होगा.

जिम या डाइटिंग के बिना भी तेजी से घटा सकते हैं वजन

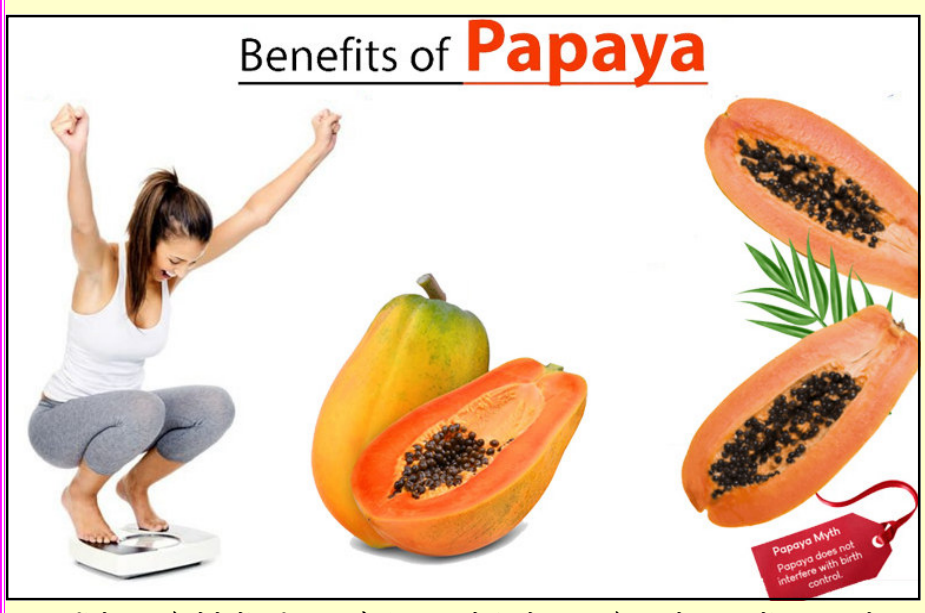

आजकल खराब खानपान और लाइफस्टाइल की वजह से वजन बढऩा और मोटापा आम समस्या बन चुकी है. इसकी वजह से तोंद बाहर निकल आता है, जो पर्सनालिटी को भद्दा बनाता है. यही कारण है कि वजन कम करने लोग हर तरकीब आजमाते हैं. कई-कई घंटे जिम में पसीना बहाते हैं, डाइटिंग करते हैं. बावजूद इसके वजन कम नहीं हो पाता है. ऐसे में पपीता आपके लिए फायदेमंद हो सकता है. यह वेट लॉस में मददगार हो सकता है. पपीते में कई ऐसे पोषक तत्व होते हैं, जो वजन कंट्रोल करने में मददगार होते हैं. इसमें फाइबर की मात्रा ज्यादा और कैलोरी काफी कम होती है. इस कारण चर्बी घटाने और वजन कम करने में पपीता को कोई तोड़ नहीं है. इसे चार तरह से अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं...

पपीते के जूस बनाकर पिएं

अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो पपीते का जूस बनाकर पी सकते हैं. इसमें मौजूद पोषक तत्व शरीर की चर्बी घटाकर फिटनेस को अच्छा बनाता है. पपीते का सेवन पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने का काम करता है.

ब्रेकफास्ट में पपीता शामिल करें

वजन कम करने के लिए ब्रेकफास्ट में पपीता शामिल करना चाहिए. इससे शरीर को एनर्जी मिलती है और एक्स्ट्रा चर्बी कम होती है. सुबह के नाश्ते में पपीते को स्लाइट में काटकर उस पर काला नमक और काली मिर्च डालकर भी खा सकते हैं.

दूध और पपीते का सेवन

ब्रेकफास्ट में कुछ हैवी खाना है तो दूध और पपीता खाना फायदेमंद हो सकता है. मिक्सी में एक गिलास दूध और पपीते के स्लाइस डालकर उसे ब्लेंड करें. कुछ ड्राई फ्रूट्स और नट्स भी डाल सकते हैं. इससे पेट लंबे समय तक भरा रहता है और बार-बार भूख नहीं लगती है. जिससे वजन कम हो जाता है.

पपीता और दही खाएं

पपीते को दही के साथ मिलाकर खाना भी फायदेमंद माना जाता है. यह स्वाद से भरपूर और वजन घटाने में मददगार होता है. एक बाउल दही में पपीता और ड्राई फ्रूट्स मिलाकर उसका सेवन कर सकते हैं. इससे शरीर को पोषक तत्व मिलता है और वजन भी तेजी से घट सकता है.

सेब खाने के फायदे तो जानते होंगे अब जान लें नुकसान

सेब खाना यूं तो हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं जिनसे हमें बचना चाहिए.

एन एप्पल इन ए डे कीप डॉक्टर अवे... यह कहावत तो आपने बहुत सुनी होगी कि दिन में एक सेब खाने से हम डॉक्टर से दूर रह सकते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें एप्पल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह एप्पल सेहत के लिए हानिकारक भी हो सकते हैं. तो चलिए हम आपको बताते हैं एप्पल खाने के फायदे और इसके साइड इफेक्टके बारे में. सेब में विटामिन सी, पोटैशियम और डाइटरी फाइबर जैसे जरूरी विटामिन और खनिज होते हैं. इतना ही नहीं ये क्वेरसेटिन, कैटेचिन और क्लोरोजेनिक एसिड जैसे एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो कोशिकाओं को नुकसान से बचाने में मदद करते हैं. सेब में डाइटरी फाइबर होते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं. इसमें मौजूद पॉलीफेनॉल ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है. कैलोरी कम होने के कारण यह वेट लॉस करने वाले लोगों के लिए बढिय़ा स्नैक ऑप्शन है. इसमें पेक्टिन होता है, यह प्रकार का प्रीबायोटिक फाइबर है जो पेट में अच्छे बैक्टीरिया को पोषण देता है, जिससे पाचन बेहतर होता है. सेब में मौजूद विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करते हैं. कुछ लोगों को सेब खाने से एलर्जी हो सकती है, खासकर ओरल एलर्जी सिंड्रोम वाले लोग अगर ज्यादा मात्रा में सेब का सेवन करें तो इससे मुंह, गले और त्वचा में खुजली या सूजन हो सकती है. बहुत ज्यादा सेब खासकर इसका छिलका खाने से पेट फूलना, गैस या पेट में ऐंठन हो सकती है. सेब थोड़े से अम्लीय होते हैं ऐसे में ज्यादा सेब खाने से एसिड रिफ्लेक्ट या पेट अपसेट हो सकता है. सेब का जूस एंटीहिस्टामाइन और एंटीबायोटिक जैसी कुछ दवाओं के अब्जॉर्प्शन में बाधा पैदा कर सकता है. वहीं, सेब खाने के बाद मूली, खट्टे फल, अचार खाने से हमेशा बचना चाहिए. आजकल मार्केट में ऐसे सेब भी खूब मिलते हैं जिसमें केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, ये थोड़े सस्ते होते हैं. लेकिन हमें इनका सेवन करने से बचना चाहिए.

सुबह की एक गलती बन सकती है सिर-गर्दन के कैंसर की वजह

सिर और गर्दन के कैंसर से बचना चाहते हैं तो रोजाना ब्रश और फ्लॉसिंग करें. इससे मसूढ़ों से जुड़ी कई बीमारी हो सकती है. यह दावा एक रिसर्च में की गई है. ओरल हेल्थ को लेकर लापरवाही से बचने की सलाह दी गई है.

सुबह की एक गलती सिर और गर्दन के कैंसर का रिस्क बढ़ा सकती है. एक नई स्टडी में पता चलता है कि रेगुलर तौर से अपने दांतों को ब्रश करने और फ्लॉसिंग करने से इन दोनों ही कैंसर का खतरा कम हो सकता है.

अध्ययन के अनुसार, मुंह की साफ-सफाई न करने से सिर्फ डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर ही नहीं बल्कि सिर और गर्दन के कैंसर का खतरा भी बढ़ सकता है. इसलिए ओरल हेल्थ को लेकर किसी तरह की लापरवाही न बरतें.

क्या कहती है स्टडी

यह स्टडी कैंसर के खतरे और मुंह में कुछ बैक्टीरिया के बीच कनेक्शन की पहचान के लिए की गई थी. एनवाईयू लैंगोन हेल्थ और इसके पर्लमटर कैंसर सेंटर के रिसर्चर के नेतृत्व में हुई इस स्टडी में पाया गया कि मुंह में रहने वाले सैकड़ों में से एक दर्जन से ज्यादा प्रकार के बैक्टीरिया सिर और गर्दन स्क्वैमस सेल ग्रोथ की आशंका 50 प्रतिशत तक बढ़ा देती हैं, जबकि छोटे अध्ययनों ने मुंह में कुछ बैक्टीरिया को कैंसर से जोड़ा है.

स्टडी में हेल्दी पुरुषों और महिलाओं से जमा ओरल जर्म्स की जेनेटिक स्ट्रक्चर को देखा गया. मुंह में नियमित रूप से पाए जाने वाले सैकड़ों अलग-अलग बैक्टीरिया में से 13 प्रजातियों को एचएनएससीसी के जोखिम को बढ़ाने या कम करने के लिए दिखाया गया है. कुल मिलाकर, इस ग्रुप में कैंसर की आशंका 30 प्रतिशत अधिक थी. मसूड़ों की बीमारी में अक्सर देखी जाने वाली 5 अन्य प्रजातियों के कॉम्बिनेशन में जोखिम 50 प्रतिशत बढ़ गया था.

क्या कहते हैं रिसर्चर

ये बैक्टीरिया बायोमार्कर के तौर पर काम कर सकते हैं, जिनसे हाई रिस्क की पहचान की जा सकती है. क्राक का कहना है कि पिछली जांचों में पहले से ही इन कैंसर से पीड़ित लोगों के ट्यूमर के सैंपल में कुछ बैक्टीरिया का पता चला था. फिर, 2018 में मौजूदा रिसर्च टीम ने पता लगाया कि हेल्दी पार्टिसिपेंट्स में रोगाणु, समय के साथ, एचएनएससीसी के आने वाले जोखिम में कैसे मदद कर सकते हैं. हालांकि, इसे लेकर अभी और भी ज्यादा रिसर्च की जरूरत है.

पुष्पराज की आंधी में उड़ा बॉक्स ऑफिस, सबसे तेज 500 करोड़ कमाने वाली फिल्म बनी

अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक थी. उम्मीद के मुताबिक थिएटर में रिलीज होते ही फिल्म ने धमाके पर धमाके करना शुरु कर दिए हैं. पहले ही दिन फिल्म ने आरआरआर के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए घरेलू बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्डतोड़ कलेक्शन करते हुए 175 करोड़ कमाए. वहीं वर्ल्डवाइड भी इसने सभी भारतीय फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 294 करोड़ की कमाई की. पुष्पा 2 की बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए मेकर्स ने पेड प्रीव्यू शो भी चलाए जिससे भी उन्होंने जमकर नोट छापे. पुष्पा 2 के पेड प्रीव्यू की कमाई 10.65 करोड़ हुई. वहीं फिल्म का दो दिनों का कलेक्शन 250 करोड़ के पार हो गया और वर्ल्डवाइड इसने 400 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया. आइए जानते हैं फिल्म की तीसरे दिन की कमाई.

पुष्पा 2 दुनियाभर के सिनेमाघरों में 5 दिसंबर को रिलीज हुई और इसने जबरदस्त ओपनिंग करते हुए 175 करोड़ की कमाई की. वहीं दूसरे दिन इसने 93.8 करोड़ रुपये कमाए और अब तीसरे दिन फिल्म ने धुआंधार कमाई करते हुए 115 करोड़ का कलेक्शन किया. इसी के साथ फिल्म का तीन दिनों का कलेक्शन 383.7 करोड़ हो गया है. यह कलेक्शन पेड प्रीव्यू समेत है. फिल्म ने तीसरे दिन तेलुगु में 31.5 करोड़, हिंदी में 73.5 करोड़, तमिल में ? 7.5 करोड़, कन्नड़ में 0.8 करोड़ और मलयालम में 1.7 करोड़ का कलेक्शन किया है.

पुष्पा 2 ने भारत के साथ दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर भी जमकर पैसा छापा है. अल्लू अर्जुन की फिल्म ने पहले दिन रिकॉर्डतोड़ 294 करोड़ का ओपनिंग कलेक्शन किया था और अब फिल्म दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है. इसी के साथ पुष्पा 2 ने सबसे तेज 500 करोड़ का आंकड़ा पार करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है. अभी रविवार के आंकड़े आना बाकी है.

अभी पुष्पा 2 का पहला वीकेंड पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुआ और इसने कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिये हैं. आरआरआर को पछाड़ सबसे बड़ी ओपनिंग, जवान को पछाड़ हिंदी में सबसे बड़ी ओपनिंग और वर्ल्डवाइड भी फिल्म सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है. वहीं अब फिल्म ने अब तक सबसे तेज 500 करोड़ भी वर्ल्डवाइड कमा लिए. अब मेकर्स की नजरें वीकेंड कलेक्शन पर है जिसमें उन्हें उम्मीद है कि फिल्म दुनियाभर में 700 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी. अगर कलेक्शन की रफ्तार ऐसी ही रही तो फिल्म जल्द ही 1000 करोड़ा का आंकड़ा पार करने वाले क्लब में शामिल हो जाएगी.

वरुण धवन की बेबी जॉन के ट्रेलर की रिलीज डेट से उठा पर्दा, धांसू पोस्टर शेयर कर बताई तारीख

2024 खत्म होने को है और दिसंबर का महीना एक के एक बाद मास एंटरनेटर देकर दर्शकों का मनोरंजन कर रहा है. अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा ही रही है. अब इसी बीच वरुण धवन की बेबी जॉन भी 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में आने के लिए तैयार है. अब हाल ही में इसके ट्रेलर की रिलीज डेट से पर्दा उठाते हुए मेकर्स ने बताया कि आखिर बेबी जॉन का ट्रेलर कब देखने को मिलेगा.

वरुण धवन की बेबी जॉन साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है फिल्म क्रिसमस के मौके पर यानि 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. इस मास एंटरटेनर के ट्रेलर की रिलीज डेट भी अब मेकर्स ने बता दी है. बता दें इसके लिए आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि बेबी जॉन का ट्रेलर कल ही यानि 9 दिसंबर को रिलीज होने जा रहा है. हाल ही में फिल्म के डायरेक्टर एटली ने सोशल मीडिया पर नया पोस्टर रिलीज करते हुए ट्रेलर की डेट बताई. पोस्टर में वरुण खूंखार लुक में नजर आ रहे हैं. पोस्टर शेयर करते हुए कैप्शन लिखा, द काउंटडाउन शुरू, बेबी जॉन का एक्शन दिखने के लिए तैयार हो जाइए, ट्रेलर कल रिलीज होगा, बेबी जॉन सिनेमाघरों में 25 दिसंबर को रिलीज होगी.

दर्शकों ने बेबी जॉन के टीजर को जबरदस्त रिस्पॉन्स दिया था. टीजर की शुरुआत एक बच्ची से होती है जो अपने पापा जो कि वरुण धवन हैं के बारे में बताती हैं. दूसरी तरफ वरुण एक पुलिस ऑफिसर के रुप में फुल एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं. इसमें जैकी श्रॉफ बतौर विलेन नजर आएंगे जिनका लुक भी टीजर में काफी खूंखार था. बेबी जॉन में कीर्ति सुरेश और वामिका गब्बी का भी अहम रोल है उनकी झलक भी टीजर में देखने को मिली. बेबी जॉन से कीर्ति बॉलीवुड में शुरुआत करने जा रही हैं. बता दें बेबी जॉन एटली की फिल्म थेरी का रीमेक है जो 2016 में रिलीज हुई थी इसमें थलापति विजय और सामंथा ने लीड रोल किया था. बेबी जॉन को कलीश ने लिखा और डायरेक्ट किया है. वरुण के साथ फिल्म में कीर्ति सुरेश, वामिका गब्बी, जैकी श्रॉफ और राजपाल यादव भी नजर आएंगे.

डिस्पैच का ट्रेलर रिलीज, पत्रकार बन देश के सबसे बड़े घोटाले का पर्दाफाश करेंगे मनोज बाजपेयी

अभिनेता मनोज बाजपेयी पिछली बार फिल्म भैयाजी में नजर आए थे। उनकी यह फिल्म भले ही ओटीटी पर कुछ खास नहीं चली, लेकिन मनोज ने अपनी उम्दा अदकारी से एक बार फिर दर्शकों का दिल जीत लिया।पिछले कुछ समय से उनकी फिल्म डिस्पैच चर्चा में है, जिसमें उन्होंने एक निडर पत्रकार की भूमिका निभाई है।इस फिल्म से जुड़ीं अब तक तमाम जानकारियां सामने आ चुकी हैं और अब इसका ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है।

ट्रेलर की शुरुआत मनोज से होती है, जो डिस्पैच नाम के अखबार में क्राइम पत्रकार हैं।वह देश के सबसे बड़े 8,000 करोड़ रुपये के घोटाले का पर्दाफाश करने वाले हैं। यह जीडीआर 2जी का घोटाला ऐसा है, जो तार टी20 मैच से भी जुड़े हैं। ट्रेलर में रोमांच का जबरदस्त तडक़ा लगाया गया है।ट्रेलर से इतना तो साफ हो गया है कि मनोज एक बार फिर अपनी दमदार अदाकारी से दर्शकों का दिल जीतने के लिए तैयार हैं। डिस्पैच का प्रीमियर बीते दिनों गोवा में आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में किया गया था। वहां फिल्म को खूब तारीफ मिली थी।इससे पहले फिल्म का टीजर और पोस्टर भी रिलीज किया गया था, जिसके बाद से ही यह उत्सकुता बनी हुई थी कि मनोज इस बार क्या नया लेकर आ रहे हैं।बता दें कि कनु बहल ने इस फिल्म का निर्देशन किया है।यह फिल्म 13 दिसंबर को ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर स्ट्रीम होगी।

प्रियंका चोपड़ा हिंदी सिनेमा में वापसी को तैयार

बॉलीवुड से हॉलीवुड तक अपने अभिनय का परचम लहराने वाली अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा इन दिनों भारतीय सिनेमा में अपनी वापसी को लेकर चर्चा में हैं।उन्हें आखिरी बार हिंदी फिल्म द स्काई इज पिंक में देखा गया था, जिसमें वह फरहान अख्तर के साथ नजर आईं। यह फिल्म 2019 में रिलीज हुई थी और प्रियंका पिछले 5 साल से हिंदी सिनेमा से दूर हैं।अब प्रियंका ने हिंदी फिल्म करने के संकेत दिए हैं। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा।

प्रियंका ने कहा, मैं कई निर्माताओं से मिलती हूं और कहानी पढ़ती हूं। हिंदी फिल्मों में मैं अलग तरह का रोल तलाश रही हूं। यह साल मेरे लिए वाकई बहुत व्यस्त रहा, लेकिन मेरे पास कुछ है। मैं आप सब लोगों को जल्द बताऊंगी।इसके अलावा जब प्रियंका से फिल्म जी ले जरा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। फरहान ने अपनी फिल्म जी ले जरा की घोषणा 2021 में की थी, लेकिन अभी तक उनकी यह फिल्म शुरू नहीं हो पाई है।इसकी स्टाकरस्ट और कहानी से जुड़ीं कई जानकारियां सामने आ चुकी हैं, वहीं कई बार फिल्म के डिब्बा बंद होने की खबरें भी सामने आईं। हालांकि, फिल्म को ठंडे बस्ते में डालने की खबरों को फरहान नकार चुके हैं।इस फिल्म में प्रियंका के साथ आलिया भट्ट और कैटरीना कैफ भी नजर आएंगी।

बांग्लादेश में हिंदू निशाने पर! कब सुधरेंगे हालात?

मनोज कुमार अग्रवाल

बांग्लादेश में युनूस सरकार कट्टरपंथी तत्वों के बेहद दबाव में है यही वजह है कि वहां अल्पसंख्यक खास कर हिन्दू समुदाय का जीवन दुश्वार हो गया है। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा के मामले में बांग्लादेश सरकार ने एक्शन लेने की शुरुआत की है. मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने ऐसे 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन पर हिंदू मंदिर और हिंदू समुदाय के लोगों के घरों में तोड़फोड़ करने का आरोप है। हालांकि जानकार लोग इस कार्रवाई को महज खानापूर्ति बता रहे हैं वहां पुलिस और सेना की मौजूदगी में हिन्दू समुदाय के लोगों पर कट्टरपंथी कहर ढा रहे हैं।

आप को बता दें कि बांग्लादेश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने 4 आरोपियों की गिरफ्तारी उत्तरी बांग्लादेश के सुनामगंज जिले से की है. पुलिस ने 12 नामजद लोगों के अलावा 150 से 170 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है. पकड़ गए चारों आरोपियों के नाम अलीम हुसैन (19), सुल्तान अहमद राजू (20), इमरान हुसैन (31) और शाहजहां हुसैन (20) बताए जा रहे हैं. इन पर सुनामगंज जिले के दोराबाजार इलाके में तोड़फोड़ करने का आरोप है.दें कि 3 दिसंबर को बांग्लादेश के सुनामगंज जिले के आकाश दास ने एक फेसबुक पोस्ट किया था. इस पोस्ट के बाद जिले में तनाव पैदा हो गया था. हालांकि, आकाश ने बाद में पोस्ट डिलीट कर दिया था. लेकिन, उपद्रवियों ने पोस्ट के स्क्रीनशॉट शेयर करने शुरू कर दिए थे, जिसके कारण इलाके में हिंसा भड़क गई थी।

हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि हम बांग्लादेश सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा देगी। वहां अल्पसंख्यकों के साथ जो कुछ भी किया जा रहा है वो परेशान करने वाला है। एस जयशंकर का यह बयान उस वक्त आया जब गुरुवार को एक 17 साल की हिंदू बांग्लादेशी लड़की नदी तैरकर अवैध रूप से भारत में घुस गई थी। इस लड़की का कहना था कि इस्कॉन भक्त होने की वजह से उसे वहां कट्टरपंथी परेशान कर रहे थे। विदित है कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद से हिंदुओं के खिलाफ धार्मिक हिंसा के मामले लगातार बढ़े हैं। सेंटर फॉर डेमोक्रेसी, प्लुरलिज्म एंड ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट के मुताबिक 5 से 9 अगस्त के बीच ही बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ लूटपाट की 190 घटनाएं सामने आई थीं।साथ ही 32 घरों में आगजनी, 16 मंदिरों में तोड़-फोड़ और यौन हिंसा के 2 मामले सामने आए थे। रिपोर्ट के मुताबिक 20 अगस्त तक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के कुल 2010 मामले सामने आए। हिंदू परिवारों पर हमले के 157 और मंदिरों के अपमान के 69 मामले शामिल थे।

दुर्गा पूजा के दौरान भी बांग्लादेश में पंडालों को निशाना बनाया गया था। इसके अलावा मूर्तियों को खंडित करने की कई घटनाएं भी दर्ज की गई थीं।

कुछ दिन पहले बांग्लादेश के ढाका में इस्कॉन नमहट्टा सेंटर को जला दिया गया था। हमले में श्री श्री लक्ष्मी नारायण देवता की मूर्तियों समेत मंदिर का सामान पूरी तरह से जल गया था।

राजद्रोह के आरोप में यूनुस सरकार ने इस्कॉन संत चिन्मय कृष्ण दास को 25 नवंबर को गिरफ्तार किया था। चिन्मय प्रभु पर उनकी एक रैली के दौरान नेशनल फ्लैग (राष्ट्रध्वज) के अपमान का आरोप लगा था। ये रैली 25 अक्टूबर को चटगांव के लाल दीघी मैदान में हुई थी।ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने पोस्ट करने वाले आकाश दास को उसी दिन हिरासत में ले लिया था. पोस्ट से भड़के उपद्रवियों ने उसे उसी दिन पुलिस की हिरासत से छीनने को कोशिश भी की थी. हालांकि, सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने आकाश को दोराबाजार की जगह सदर पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर दिया था. गुस्साए उपद्रवियों ने उस दिन ही लोकनाथ मंदिर और हिंदू समुदाय के घरों-दुकानों पर हमला किया था।

बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध उस समय तनावपूर्ण हो गए थे, जब शेख हसीना 5 अगस्त को छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के बाद देश छोड़कर भारत आ गई थीं. हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद वहां मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार सत्ता संभाल रही है.

बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद हिंदुओं पर हमले एकदम से बढ़ गए हैं. वहां, हिंतुओं और खासतौर पर इस्कॉन के सदस्यों को निशाना बनाया जा रहा है. कुछ दिनों पहले बांग्लादेश की पुलिस ने बांग्लादेश सम्मिलिता सनातनी जागरण जोत संगठन के प्रवक्ता हिंदू भिक्षु चिन्मय कृष्ण दास को भी गिरफ्तार कर लिया था, जो अब भी जेल में हैं। रैली के बाद वकील नेता फिरोज खान ने चिन्मय प्रभु और अन्य लोगों के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। दरअसल रैली के दौरान कुछ लोगों ने आजादी स्तंभ पर बांग्लादेश के नेशनल फ्लैग से ऊपर सनातन जागरण मंच का ध्वज फहरा दिया था। बांग्लादेश में नेशनल फ्लैग से ऊपर कोई और फ्लैग फहराना देशद्रोह माना जाता है।

संत चिन्मय कृष्ण दास ने बांग्लादेशी हिंदुओं पर हुए अत्याचार के खिलाफ लोगों को एकजुट किया था।चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के बाद चटगांव में हिंसा फैल गई थी। इस हिंसा में एक वकील की भी मौत हुई थी। वकील की मौत के बाद एक बार फिर चिन्मय प्रभु और अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में 164 नामजद और लगभग 500 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। इस्कॉन पर बैन लगाने के लिए केस भी दायर

बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार गिरने के बाद हिंदू आबादी निशाने पर है। मंदिरों पर हमले हो रहे हैं। हिंदू नेताओं को धमकियां मिल रही हैं। कट्टरपंथी मुस्लिम इस्कॉन पर बैन लगाना चाहते हैं। इसे लेकर केस भी दायर किए गए हैं।

बांग्लादेश सरकार द्वारा हिन्दुओं पर हमले के चार आरोपियों को गिरफ्तार कर भारत और विश्व के कई देशों में बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रही हिंसा के विरोध को देखते हुए नामचार कारवाई की है ताकि बढ़ती असंतोष को कम किया जा सके। हकीकत यह है कि बांग्लादेश की युनूस सरकार पूरी तरह कट्टरपंथी लोगों के दबाव में है और हिन्दुओं को संरक्षण देने में नाकाम रही है। भारत सरकार अभी सिर्फ अनुकूल स्थिति का इंतजार कर रही है निकट भविष्य में बांग्लादेश को सबक सिखा सकती है।

इच्छा शक्ति से ही नियंत्रित हो सकेगा प्रदूषण

हम और आप जब भी कोई वाहन ख़रीदते हैं तो हम उस वाहन की क़ीमत के साथ-साथ रोड टैक्स, जीएसटी आदि टैक्स भी देते हैं। इन सब टैक्स देने का मतलब हुआ कि यह सब राशि सरकार की जेब में जाएगी और घूम कर जनता के विकास के लिए इस्तेमाल की जाएगी। परंतु रोड टैक्स के नाम पर ली जाने वाली मोटी रक़म क्या वास्तव में जनता पर ख़र्च होती है? बीते कुछ सप्ताह से दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत को प्रदूषण के बादलों ने घेर रखा है। इससे आम जीवन अस्त-व्यस्त हो चुका है। प्रदूषण की रोकथाम को लेकर सरकार ने कई तरह की पाबंदियाँ लगा दी हैं। इसके चलते असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि इन पाबंदियों के चलते कई रोज़गारों पर भी असर पडने लगा है। निर्माण कार्य में लगे दिहाड़ी मज़दूर वर्ग इन पाबंदियों के चलते सबसे अधिक परेशान है। तमाम टीवी चैनलों पर प्रदूषण के बिगड़ते स्तर पर काफ़ी बहस हो रही है। परंतु क्या किसी ने हमारे देश में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सही व ठोस कदम उठाने की बात की है? क्या केवल निर्माण कार्यों और वाहनों पर प्रतिबंध से प्रदूषण के स्तर में कमी आएगी? ऐसे अनेकों कारण हैं जिन पर अगर सरकार ध्यान दे तो प्रदूषण में नियंत्रण पाया जा सकता है। सबसे पहले बात करें वाहन प्रदूषण की। इस बात पर इसी कॉलम में कई बार लिखा जा चुका है कि एक विशेष आयु या श्रेणी के वाहन को प्रतिबंध करने से क्या प्रदूषण में कमी आएगी? इसका उत्तर हाँ और नहीं दोनों ही है। यदि कोई वाहन, जो कि पुराने माणकों पर चल रहा है और उसके पास वैध पीयूसी प्रमाण पत्र नहीं है तो निश्चित रूप से ऐसे वाहन को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। परंतु यदि वही वाहन प्रदूषण के तय माणकों की सीमा में पाया जाता है तो उसे प्रतिबंधित करने का क्या औचित्य है? हम और आप जब भी कोई वाहन ख़रीदते हैं तो हम उस वाहन की क़ीमत के साथ-साथ रोड टैक्स, जीएसटी आदि टैक्स भी देते हैं। इन सब टैक्स देने का मतलब हुआ कि यह सब राशि सरकार की जेब में जाएगी और घूम कर जनता के विकास के लिए इस्तेमाल की जाएगी। परंतु रोड टैक्स के नाम पर ली जाने वाली मोटी रक़म क्या वास्तव में जनता पर ख़र्च होती है? क्या हमें अपनी महँगी गाडियों को चलाने के लिए साफ़-सुथरी और बेहतरीन सडक़ें मिलती हैं? टूटी-फूटी सडक़ों की समय-समय पर मरम्मत होती है? क्या देश भर में सडक़ों की मरम्मत करने वाली एजेंसियाँ अपना काम पूरी निष्ठा से करतीं हैं? इनमें से अधिकतर सवालों के जवाब आपको नहीं में ही मिलेंगे। टूटी-फूटी सडक़ों पर वाहन अवरोधों के साथ चलने पर मजबूर होते हैं, नतीजा जगह-जगह ट्रैफिक़ जाम हो जाता है। ऐसे जाम में खड़े रहकर आप न सिर्फ़ अपना समय ज़ाया करते हैं बल्कि महँगा ईंधन भी ज़ाया करते हैं। जितनी देर तक जाम लगा रहेगा, आपका वाहन बंपर-टू-बंपर चलेगा और बढ़ते हुए प्रदूषण की आग में घी का काम करेगा। ऐसे में जिन वाहनों को पुराना समझ कर प्रतिबंधित किया जाता है, उनसे कहीं ज़्यादा मात्रा में नये वाहनों द्वारा प्रदूषण होता है। इसलिए लोक निर्माण विभाग या अन्य एजेंसियों की यह ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि वह सडक़ों को दुरुस्त रखें जिससे प्रदूषण को बढ़ावा न मिले। इसके साथ ही ट्रैफिक़ नियंत्रण की समस्या भी एस समस्या है जिससे प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है। मिसाल के तौर पर आपको आपके शहर में ऐसे कई चौराहे मिल जाएँगे जहां लाल-बत्ती की अवधि ज़रूरत और ट्रैफिक़ के प्रवाह के अनुसार मेल नहीं खाती। नतीजा, ऐसे चौराहों पर ट्रैफिक़ की लंबी क़तारें। ऐसा नहीं है कि पूरा दिन ही ऐसे चौराहों पर लंबी क़तारें लगती हैं। ज़्यादातर क़तारें ट्रेफिक के पीक घंटों में लगती हैं। यदि उस समय ट्रैफिक़ पुलिस द्वारा चुनिंदा चौराहों को नियंत्रित किया जाए तो जाम की समस्या पर आसानी से क़ाबू पाया जा सकता है। इसके लिए कुछ मामूली से ही परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। आज गूगल मैप पर आप घर बैठे ही हर गली नुक्कड़ का ट्रैफिक़ देख सकते हैं। यदि ्लान कर सकते हैं तो ट्रैफिक़ कंट्रोल रूम के अधिकारी, संबंधित इलाक़े के ट्रैफिक़ अधिकारी को इस समस्या के प्रति झकझोर क्यों नहीं सकते? ट्रैफिक़ को नियंत्रित करने के जैसे, ही प्रदूषण के अन्य कारकों पर भी लगाम कसी जा सकती है। ज़रूरत है तो इच्छा शक्ति की। यहाँ आपको याद दिलाना चाहूँगा कि 2010 में जब हमारे देश में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन हुआ था तो दिल्ली में एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई थी कि ट्रैफिक़ जाम नहीं होते थे। जगह-जगह पर ट्रैफिक़ पुलिस के सिपाही ट्रैफिक़ पर पैनी नजऱ बनाए हुए थे। यानी डंडे के ज़ोर पर व्यवस्था को नियंत्रित किया जा रहा था। यदि एक ट्रैफिक़ की समस्या को डंडे के ज़ोर पर, किसी विशेष इंतज़ाम के लिए नियंत्रित जा सकता है तो आम दिनों में क्यों नहीं? अब बात करें दीपावली के बाद हर वर्ष होने वाली पराली जलाए जाने की। यह बात जाग-ज़ाहिर है कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान हर वर्ष इन्हीं दिनों पराली जलाते हैं। यह समस्या हर वर्ष प्रदूषण का कारण बनती है। हर वर्ष बड़ी-बड़ी बातें और घोषणाएँ की जाती हैं लेकिन इस समस्या के समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते। यदि कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन हो या कोविड के दौरान लॉकडाउन लागू करना हो, जब इन्हें सख़्ती से लागू किया जा सकता है तो पराली को जलाने से क्यों नहीं रोका जा सकता? ठीक उसी तरह कारख़ानों से निकलने वाले धुएँ को भी नियंत्रित करना असंभव नहीं है। सरकार चाहे तो इस राह में ठोस कदम उठा कर प्रदूषण को नियंत्रण में ला सकती है। केवल नारों, घोषणाओं और प्रतिबंधों से नहीं इच्छा शक्ति से ही नियंत्रित हो सकेगा प्रदूषण। जहां चाह वहाँ राह!

लूट के लिए डोईवाला के प्रापर्टी डीलर की हरिद्वार में हत्या

-6 दिन बाद खेत में गडा मिला शव, 2 आरोपी गिरफ्तार, एक फरार
-फरार आरोपी की तलाश में लगी पूलिस

हरिद्वार । पिछले 6 दिन से लापता चल रहे डोईवाल के प्रॉपर्टी डीलर के साथ अनहोनी हो गई है। हरिद्वार के खानपुर में प्रॉपर्टी डीलर का शव मिला है। पुलिस के अनुसार रामशंकर की हत्या की गई है। हत्या लूट के लिए की गई। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी अभी फरार है। डोईवाला में कुड़कावाला के रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर रामशंकर 8 दिसंबर को अपने घर से हरिद्वार के लिए निकले थे। रामशंकर का हरिद्वार के खानपुर में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम था। उसी दिन दोपहर बाद से उनका उनका मोबाइल स्विच ऑफ आने लगा और परिवार वालों से उनका संपर्क नहीं हो पा रहा था। काफी पता करने के बाद भी जब उनका पता नहीं चला तो परिवार वालों ने खानपुर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी।

प्रॉपर्टी डीलर रामशंकर का शव शुक्रवार को पुलिस ने खानपुर के इंद्रपुरी के खेत से बरामद कर लिया है। बताया जा रहा है कि तीन लोगों ने रामशंकर को अकेला पाकर मारपीट की। इन बदमाशों ने उनसे पैसे लूटने का प्रयास किया। विरोध करने पर रामशंकर की हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को रेत में दबा दिया। पुलिस के सामने दोनों आरोपियों ने अपना जुल्म कबूल कर लिया है। दोनों आरोपियों ने अपने नाम रॉबिन पुत्र कमल सिंह ओर दूसरे ने अपना नाम अक्षय पुत्र प्रेम सिंह बताया। वहीं तीसरा आरोपी जो कि फरार है अंकित पुत्र अमरपाल है, जिसकी तलाश की जा रही है।

पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर शव को बरामद कर लिया है। पुलिस ने आज जब शव निकाला तो हाथ पैर भी बंधे मिले हैं।

रुड़की के सरकारी अस्पताल में शव के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई है। पुलिस के अनुसार लूट की नीयत से निर्मम हत्या की गई। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी फरार है। परिजनों ने बताया कि जिन लोगों ने रामशंकर की निर्ममता से हत्या की है, उन्हें वो अपने खेत का कार्य करने के लिए देते थे। रामशंकर की हत्या से पूरे डोईवाला में शोक की लहर है।

इसके बाद पुलिस ने एक टीम गठित की। गठित टीम द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत सभी आने जाने वाले रास्तों के सीसीटीवी को चेक किया गया। साथ ही संदिग्धों से पूछताछ सहित व्यापक प्रचार प्रसार हेतु फोटो पम्पलेट चस्पा किये गये। आज शुक्रवार को मुखबिर की सूचना पर ग्राम चन्द्रपुरी से संदिग्धों से पूछताछ की गई।

संदिग्धों द्वारा बताया गया कि गुमशुदा रामशंकर हमारे गांव में आता रहता था। उसकी हमारे गांव के आसपास जमीन भी है। हमें पता था कि रामशंकर अच्छे रुपये पैसे वाला आदमी है। 8 दिसंबर को हम दोनों अपने एक अन्य दोस्त के साथ कम्बलपुर खेतों की तरफ गये थे। वहां पर हमें रामशंकर मिल गया। उसके दूसरे दिन रॉबिन, रामशंकर का फोन लेकर रुपये निकालने के लिये मंगलौर पेट्रोल पम्प पर गया था। उसने अलग अलग कुल 30,000 (तीस हजार रुपये) निकाले थे। अगले दिन रॉबिन, रामशंकर का फोन लेकर रुपये निकालने के लिये मण्डावर बिजनौर गया। लेकिन मोबाइल फोन से रुपये नहीं निकल पाये। तीसरे दिन रॉबिन, रामशंकर के मोबाइल से रुपये निकालने के लिये मीरापुर गया था, लेकिन वहां भी रुपये नहीं निकल पाये। हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने पूरे मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि बीती 9 दिसंबर को कुड़कावाला थाना डोईवाला देहरादून निवासी रमेश चन्द पुत्र स्वर्गीय निकसाराम ने तहरीर दी गई थी। तहरीर में बताया गया कि दिनांक 8 दिसंबर से उनका बेटा रामशंकर उम्र लगभग 48 वर्ष लापता है। उन्होंने बताया कि दिन में ग्राम दूकुड़कावाला डोईवाला देहरादून से वो अपनी प्रॉपर्टी डीलिंग के आफिस निकट पेट्रोल पम्प खानपुर आया था। करीब 6. 00 बजे सायं को उसके फोन पर फोन किया गया, तो उसका फोन लगातार बन्द आ रहा था। परिजनों द्वारा फोन ना उठाए जाने के कारण चिंतित होकर पुलिस को गुमशुदगी दर्ज कराई।

डीएम के निरीक्षण पर आठ कर्मचारी अनुपस्थित मिले, वेतन रोका

हरिद्वार । जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने गुरुवार को रुड़की क्षेत्र के विभिन्न सरकारी विभागों में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान डीएम को तहसील परिसर स्थित तीन कार्यालयों में आठ कर्मचारी अनुपस्थित मिले। इस पर डीएम ने कर्मचारियों का वेतन रोकने के निर्देश संबंधित को दिए। वहीं, छापेमारी के बाद डीएम ने क्षेत्र के सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने बच्चों से अभिभावक के तौर पर संवाद स्थापित किया। शुक्रवार को डीएम ने जिले के विभिन्न कार्यालयों में छापेमारी की। डीएम की छापेमारी से सरकारी कार्यालयों में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। इस दौरान डीएम ने रुड़की स्थित एआरटीओ कार्यालय, तहसील परिसर, क्षेत्रीय खाद्य पूर्ति कार्यालय और नगर पंचायत झबरेड़ा आदि में कर्मचारियों की उपस्थित की जांच की। तहसील परिसर के विभिन्न कार्यालयों में छापेमारी के दौरान क्षेत्रीय खाद्य आपूर्ति कार्यालय में पांच कार्मिक, नजारत अनुभाग में दो कार्मिक, चकबंदी अनुभाग-2 में एक कार्मिक अनुपस्थित मिला। कुल आठ कर्मचारी अनुपस्थित मिलने पर डीएम ने अनुपस्थित कर्मचारियों का वेतन रोकते हुए कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। साथ ही नगर पंचायत झबरेड़ा को अपनी आय के संसाधन बढ़ाने और नगर पंचायत को वेतन भुगतान में आत्मनिर्भर बनाने के निर्देश दिए। वहीं, स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में निरीक्षण के दौरान डीएम ने व्यवस्थाओं, शिक्षकों की उपस्थिति, पढ़ाई की गुणवत्ता और विद्यार्थियों की उपस्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान राजकीय प्राथमिक विद्यालय कोटवाल आलमपुर में मिड डे मिल भोजन के लिए निर्धारित लिस्ट नहीं दिखा पाने पर डीएम ने नाराजगी जाहिर की। साथ ही बच्चों को सही से पका हुआ भोजन परोसने और गुणवत्तायुक्त भोजन खिलाते रहने के निर्देश दिए। आंगनबाड़ी केंद्र कोटवाल प्रथम के निरीक्षण के दौरान आंगनबाड़ी वर्कर को निर्देशित करते हुए कहा कि शुरू से ही बच्चों की झिझक दूर करने का प्रयास करें और बच्चों को शुरू से ही बोलना सिखाया जाए।

पर्याप्त पर्चियां नहीं मिलने से गन्ना किसान मायूस

हरिद्वार । पथरी क्षेत्र के दर्जनों गांवों के किसानों को समयानुसार लक्सर मील द्वारा गन्ने की पर्चियां नहीं मिल पा रही हैं। पर्चियां नहीं मिलने से किसान नाराज हैं। उनका आरोप है कि पिछले एक सप्ताह से तौल केन्द्रों पर तौल नाममात्र हो रहा है। इससे गन्ना खेतों में ही पड़ता है। गांव रानीमाजरा, शाहपुर, पदार्था, झाबरी, फेरुपुर, धनपुरा, कटारपुर, चांदपुर, बादशाहपुर, पथरी, झाबरी सहित दर्जनों गांवों के किसानों को लक्सर मील द्वारा लगाए गए गन्ना तौल केन्द्र नाममात्र चल रहे हैं। जिसके चलते किसान अपने खेतों को अन्य फसलों के लिए खाली नहीं कर पा रहे हैं। किसानों का आरोप है मील प्रबंधक की गलत नीति के चलते किसानों को समय से पर्चियां नहीं दी जा रही है। पर्चियां नहीं मिलने के कारण खेत खाली नहीं हो पा रहे हैं। किसान पवन चौहान, सुनीत चौहान, निसार अहमद, रमेश सिंह, राजबीर, शमशाद, इरशाद, बबलू, मुकर्रम, दलीप, इरफान ने बताया मील में गन्ने की मात्रा अधिक पहुंच रही है जिसके चलते कर्मचारियों के द्वारा पर्ची जारी करने में देरी हो रही है। किसान एक-एक पर्ची के लिए जूझ रहे हैं। किसानों ने मिल प्रबंधक व गन्ना समिति के डायरेक्टर से जल्द पर्चियां उपलब्ध कराने व तौल केन्द्रों पर तोल शुरू कराने की गुहार लगाई है, ताकि समय अनुसार किसान खेत खाली कर अन्य फसलों की बुवाई कर सके। लक्सर मील जीएम सुरेश राठी ने बताया किसानों को जरूरत के आधार पर पर्चियां दी जा रही है। तौल केन्द्र से गन्ना उठान में देरी के चलते तौल केन्द्र बन्द रहता है।

सुनील सेठी को मेयर प्रत्याशी बनाने की मांग

हरिद्वार । महानगर व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष सुनील सेठी ने व्यापारियों और जनता की समस्याएं सुनकर उनके निदान का भरोसा दिलाया। बैठक में मौजूद व्यापारी, सामाजिक संगठन से जुड़े लोगों ने सुनील सेठी को भाजपा से मेयर पद का उम्मीदवार बनाने की मांग की। सुनील मनोचा के संयोजन में आहुत बैठक में मुकेश अग्रवाल ने कहा कि वह ऐसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं जो जनता के द्वार तक निगम की सुविधाएं लाए और वार्डों के साथ हरिद्वार का विकास करे। उन्होंने कहा कि शहर की मुख्य समस्याओं में टूटी सड़के, आवारा पशु, पथ प्रकाश की व्यवस्थाएं, हरकी पैड़ी से भिक्षा मांगने वालों और असमाजिक तत्वों को हटाया जाना शामिल है। इसके अलावा बंदरों और कुत्तों के आतंक से छुटकारा चाहते हैं। सभी ने सुनील सेठी के सामने इन समस्याओं के निवारण की मांग की। सुनील सेठी ने आश्वस्त किया कि वो हर समस्या के निदान का प्रयास करेंगे। बैठक में मुख्य रूप से रवि बांगा, सोनू चौधरी , हरीश अरोड़ा, राकेश सिंह, एस के सैनी, अनिल कोरी, भूदेव शर्मा,विनेश शर्मा, बंटी प्रकाश, राहुल शर्मा, गगन शर्मा, सचिन अग्रवाल, आशीष शर्मा, दीपक कुमार,पंकज शर्मा, प्रमोद कुमार, राजवीर सिंह, धर्मपाल सिंह उपस्थित रहे।

संस्कृत केवल भाषा नहीं, अपितु एक जीवन शैली

हरिद्वार । उत्तराखंड संस्कृत अकादमी के तत्वावधान में संस्कृत विद्यालय, महाविद्यालयों के शिक्षकों के शिक्षण कौशल विकास के लिए तीन दिवसीय संस्कृत शिक्षक कार्यशाला का आयोजन किया गया। शुभारंभ पर संस्कृत संवर्धन प्रतिष्ठान के निदेशक मुख्यप्रशिक्षक डॉ. चांदकिरण सलूजा ने कहा कि संस्कृत केवल भाषा नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। शिक्षा का लक्ष्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है, जिसमें शिक्षक की भूमिका सर्वोपरि है। डॉ. चांदकिरण ने कहा कि शिक्षण कार्य वृत्ति नहीं अपितु सर्वोत्तम सेवा कार्य है। शिक्षा का अर्थ एक अच्छे मानव का निर्माण करना है। शिक्षक छात्रों को संस्कृत भाषा सरलतम रूप से पढ़ाने में सहयोगी बने। अकादमी के सचिव डॉ. वाजश्रवा आर्य ने कहा कि संस्कृत अकादमी प्रदेश की द्वितीय राजभाषा संस्कृत के संरक्षण संवर्धन के लिए निरंतर कार्य कर रही है, संस्कृत विद्यालय महाविद्यालय के शिक्षकों की पुनश्चर्या के लिए देश के प्रतिष्ठित संस्थान के प्रशिक्षकों के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. दिनेश चंद्र शास्त्री ने कहा कि प्रदेश की द्वितीय राजभाषा संस्कृत है। इसलिए संस्कृत विद्यालय महाविद्यालय के सभी शिक्षकों को प्रशिक्षण में भाग लेना चाहिए। अकादमी द्वारा आयोजित संस्कृत शिक्षक प्रशिक्षण दिया जाता सराहनीय हैं। कार्यशाला संयोजक किशोरी लाल रतूड़ी ने बताया कि संस्कृत सवर्धन प्रतिष्ठान दिल्ली की छह सदस्यीय टीम की ओर से तीन दिनों में 15 सत्रों के माध्यम से प्रदेश के 50 संस्कृत शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा ।

स्वामी,मुद्रक व प्रकाशक अवनीश कुमार द्वारा भगवती प्रिंटर्स,इण्डस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार से छपवाकर ग्रा. बसवाखेड़ी पो. मंगलौर, हरिद्वार (उत्तराखण्ड़) से प्रकाशित किया।
सम्पादकः अवनीश कुमार, मो0 9410553400
ई-मेलः liveskgnews@gmail.com
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र हरिद्वार न्यायालय में ही होगा)
सभी लेखों में सम्पादक की सहमति जरूरी नही है।